प्रकाशन का 44 वां वर्ष

सरोकारी पत्रकारिता के लिए समर्पित

शैल समाचार

निष्पक्ष एवं निर्भीक साप्ताहिक

ई – पेपर

www.facebook.com/shailshamachar

प्रदेश का पहला ऑनलाईन साप्ताहिक

वर्ष 44 अंक – 6 पंजीकरण आरएनआई 26040/74 डाक पजींकरण एच. पी./93 /एस एम एल Valid upto 31-12-2020 सोमवार 04 – 11 फरवरी 2019 मूल्य पांच रूपए

दस्तावेजों के आईने में प्रदेश का बजट

16 नयी योजनाओं के साथ आया 44384 करोड़ का बजट

शिमला/शैल। मुख्यमन्त्री जयराम ठाकुर का 2019-20 का कुल बजट 44384 करोड़ का होगा यह खुलासा मुख्यमन्त्री ने सदन में अपने बजट भाषण में रखा है। इस बजट में मुख्यमन्त्री ने अगले वित्त वर्ष के लिये 16 नयी योजनाओं की घोषणा की है। पिछले वित्त वर्ष में ऐसी ही 30 योजनाओं की घोषणा की गयी थी। अब यह पिछली ओर अगली दोनों योजनाएं एक साथ चलेंगीं। लेकिन पिछली 30 योजनाओं में से अधिकांश अभी तक अमली शक्ल नही ले पायी हैं। ऐसे में 31 मार्च को समाप्त होने वाले वित्त वर्ष में यह बची हुई योजनाएं आकार ले पाती है या नही इसका पता आने वाले दिनों में लगेगा। इन सारी योजनाओं के लिये धन का प्रावधान कैसे हो पायेगा यह एक गंभीर सवाल है। प्रदेश का बजट योजना और गैर योजना दो भागों में बंटा रहता है। इसमें योजना के लिये 90% की सहायता केन्द्र से मिलती है और 10% योगदान राज्य सरकार का होता है। यह योजना 2019-20 के लिये 7100 करोड़ की है। लेकिन गैर योजना का सारा खर्च राज्य को अपने ही संसाधनों से पूरा करना होता है चाहे उसके लिय कर्ज ही क्यों न लेना पड़े। वर्ष 2019-20 में प्रदेश का गैर योजना खर्च 36089.03 करोड़ होगा जबकि राजस्व आय केवल 33746.95 करोड़ रहने वाली है। इस तरह राजस्व आय से राजस्व व्यय 2342.08 करोड़ बढ़ जाता है। योजना और गैर योजना दोनों का मिलाकर राज्य की समेकित निधि बनती है।

राजस्व आय और व्यय के साथ ही बजट में पूंजीगत प्राप्तियों का ब्योरा भी रहता है। इसके मुताबिक वर्ष 2019-20 में सरकार 8330.75 करोड़ ऋणों के माध्यम से जुटायेगी। ऐसे में सवाल उठता है कि जब राजस्व आय और व्यय में केवल 2342.08 करोड़ का घाटा है तब 8330.75 करोड़ का पूंजीगत ऋण क्यों? जब योजना का आकार 7100 करोड़ है और उसमें से 90% केन्द्र देगा फिर राजस्व व्यय में योजना के नाम पर 2822.24 करोड़ का खर्च क्यों? फिर पूंजीगत प्राप्तियों में भी योजना के नाम पर केवल 3661.30 करोड़ का खर्च क्यों जबकि योजना तो 7100 करोड़ की है। बजट के आंकड़ो की इस जादूगरी से यह आंशका होना स्वभाविक है कि क्या योजना के तहत किये जा रहे कार्यो को पूरा होने के बाद भी गैर योजना में ट्रांसफर नही किया जा रहा है। क्या इसी कारण से कई कई वर्षो तक कार्यो के उपयोगिता प्रमाण पत्र जारी नहीं किये जाते हैं और हर वर्ष सीएजी की रिपोर्ट में समेकित निधि से अधिक खर्च होने का पैरा बनता है। इस आने वाले वित्त वर्ष में एफआरबीएम के तहत केवल 4524 करोड़ की ही ऋण लिया जा सकता है। ऐसे में कर्ज की सीमा 4524 करोड़ ही हो सकती है तो फिर पूंजीगत प्राप्तियों के तहत 8330.75 करोड़ का ऋण क्यों और कैसे?

प्रदेश का 2003 में कुल कर्ज 13209.47 करोड़ था जो कि बढ़कर 2017-18 में 4790.21 करोड़ हो गया है। मुख्यमन्त्री के बजट भाषण के अनुसार 2018-19 में 4546 करोड़ का ऋण लिया जायेगा। इस तरह 2018-19 में यह कर्जभार 52 हजार करोड़ से ऊपर चला जायेगा। ऐसे में यह सवाल उठना स्वभाविक है कि क्या वित्तिय प्रबन्धन केवल कर्ज का जुगाड़ करना ही रह गया है? यदि इसी तरह लोक लुभावन घोषणओं को पूरा करने के लिये कर्ज लिया जाता रहा तो मुख्यमन्त्री के इस कार्यकाल में ही यह कहां तक पहुंच जायेगा इसका अनुमान आंकड़ों और दस्तावेजों से लगाया जा सकता है।

मुख्यमन्त्री के भाषण के अंश

अध्यक्ष महोदय, अब मैं 2018-19 के संशोधित अनुमानों तथा 2019-20 के बजट अनुमानों पर आता हूँ।

वर्ष 2018-19 के संशोधित अनुमानों के अनुसार कुल राजस्व प्राप्तियां 31 हजार, 189 करोड़ रुपये हैं, जबकि 2018-19 के बजट में यह प्राप्तियां 30 हजार, 400 करोड़ रुपये अनुमानित थीं। इसी प्रकार 2018-19 के संशोधित अनुमानों के अनुसार कुल राजस्व व्यय 33 हजार, 408 करोड़ रुपये रहने का अनुमान है जबकि बजट में 33 हजार 568 करोड़ रुपये अनुमानित था। इस प्रकार संशोधित अनुमानों के अनुसार कुल राजस्व घाटा 2 हजार, 219 करोड़ रुपये रहेगा जो कि 2018-19 के बजट अनुमान से 949 करोड़ रुपये कम है। संशोधित अनुमानों के अनुसार वर्ष 2018-19 के दौरान कुल राजकोषीय घाटा 7 हजार, 786 करोड़ रुपये रहने का अनुमान है जो कि राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का 5.14 प्रतिशत है। 2018-19 के बजट अनुमानों के अनुसार कुल राजकोषीय घाटा राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का 5.16 प्रतिशत आँका गया था।

वित्तीय वर्ष 2018-19 में इस घाटे को पूरा करने के लिये 4 हजार, 546 करोड़ रुपये का शुद्ध ऋण लेने का अनुमान है, जो कि Fiscal Responsibility and Budget Management Act (FRBM) के प्रावधानों के अनुसार है।

वर्ष 2019-20 के दौरान कुल राजस्व प्राप्तियां 33 हजार, 747 करोड़ रुपये रहने का अनुमान है तथा कुल राजस्व व्यय 36 हजार, 089 करोड़ रुपये अनुमानित है। इस प्रकार कुल राजस्व घाटा 2 हजार, 342 करोड़ रुपये अनुमानित है। राजकोषीय घाटा 7 हजार, 352 करोड़ रुपये रहने का अनुमान है, जो कि प्रदेश के सकल घरेलू उत्पाद का 4.35 प्रतिशत होगा। प्राप्तियों एवं व्यय के बीच के अन्तर को ऋण के माध्यम से पोषित किया जाएगा तथा यह शुद्ध ऋण 5 हजार, 068 करोड़ रुपये रहने का अनुमान है। यह ऋण FRBM अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप ही लिये जाएंगे।

तालिका–I

II. बजट को समझने के लिए मुख्य संकेतक।

(रुपए करोड़ों में)

		वास्तविक 2017-18	बजट अनुमान 2018-19	बजट अनुमान 2019-20
क.	राजस्व प्राप्तियाँ			
	(i) राज्य प्राप्तियाँ	9471.52	10229.12	10364.29
	(ii) केन्द्रीय प्राप्तियाँ (including Central Taxes) *of which*	14965.72	15880.14	19557.26
	(a) केन्द्रीय करों में हिस्सा	4801.31	6387.00	7398.00
	(b) केन्द्रीय हस्तांतरण	10164.42	9493.14	12159.26
	(iii) केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों के अन्तर्गत अनुदान (excluding CSS loans)	2929.82	4290.95	3825.40
	योग (राजस्व प्राप्तियाँ)	27367.06	30400.21	33746.95
ख.	राजस्व व्यय			
	(i) गैर योजना	23205.93	28302.46	30747.41
	(ii) योजना	1858.06	2189.14	2519.38
	(iii) केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमें	1989.17	3076.37	2822.24
	योग (राजस्व व्यय)	27053.16	33567.97	36089.03
	निवल (राजस्व घाटा /लाभ)*	313.90	-3167.76	-2342.08
ग.	पूँजीगत प्राप्तियाँ			
	(i) सकल ऋण *(excluding W&M/overdraft but includes net PF receipts)*	6592.12	7730.20	8330.75
	(ii) ऋणों की वसूलियाँ	39.61	34.55	26.73
	(iii) पूँजीगत विविध प्राप्तियाँ	34.82	0.00	0.00
	योग (पूँजीगत प्राप्तियाँ)	6666.55	7764.75	8357.48
घ.	पूँजीगत व्यय			
	(i) ऋणों की अदायगियाँ *(excluding W&M)*	3099.71	3184.20	3261.75
	(ii) गैर योजना पूँजीगत व्यय	467.79	475.95	372.45
	(iii) योजना पूँजीगत व्यय	2842.65	2997.22	3661.30
	(iv) केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमें	947.76	1214.59	1003.20
	योग (पूँजीगत व्यय)	7357.90	7871.97	8298.70
	राजकोषीय अधिशेष/घाटा*	-3869.87	-7820.97	-7352.30

*अधिशेष (+)/घाटा(-)

तालिका–V

VI. राज्य सरकार के दायित्व ।

(रुपए करोड़ों में)

वर्ष	आन्तरिक ऋण*	केन्द्रीय सरकार से ऋण और अग्रिम	कुल लोक ऋण	जी.आई.एस./जीपीएफ इत्यादि	अंशदान पैंशन योजना	अन्य दायित्व**	कुल दायित्व
2002-03	6393.12	2521.38	8914.50	2484.42		1810.55	13209.47
2003-04	9490.41	1536.42	11026.83	2720.19		1230.54	14977.56
2004-05	12299.79	1097.61	13397.40	2981.02		1279.98	17658.40
2005-06	12868.46	1070.60	13939.06	3291.11		1442.81	18672.98
2006-07	13475.99	1019.57	14495.56	3613.14	1.11	1688.50	19798.31
2007-08	13808.36	1014.78	14823.14	4153.56	28.99	2236.15	21241.84
2008-09	15219.00	970.88	16189.88	4668.44	95.64	2197.43	23151.39
2009-10	16611.70	983.85	17595.55	5214.11	155.99	198.09	23163.74
2010-11	17533.13	959.65	18492.78	6102.36	183.17	182.54	24960.85
2011-12	18428.24	947.16	19375.40	6737.90	238.27	142.50	26494.07
2012-13	19624.27	1018.37	20642.64	7849.64	88.51	126.50	28707.29
2013-14	21647.06	1012.42	22659.48	8736.31	46.77	0.00	31442.56
2014-15	24127.33	1070.73	25198.06	9921.47	32.07	0.00	35151.60
2015-16	26860.87	1058.69	27919.56	10639.90	8.36	0.00	38567.82
2016-17	31493.97	1076.30	32570.27	11844.41	8.05	0.00	44422.73
2017-18	33591.41	1079.30	34670.71	13236.38	-0.89	0.00	47906.21

*इन आकड़ों में एस0एल0आर0 उधार, एन0एस0एस0एफ0 नाबार्ड, हुडको, एच0एफ0डी0सी0, एल0आई0सी0, एन0सी0डी0सी0, जी0आई0सी0 इत्यादि के रूप में बाज़ार से लिए गए ऋण, नान एस0एल0आर0 उधार और लोक लेखा के अन्तर्गत शीर्ष 8448 में रखी गई ब्याज सहित राशियाँ सम्मिलित है।

**इसमें राज्य सरकार के उपक्रमों द्वारा लिए गए ऋण का दायित्व भी सम्मिलित है ।

मुख्यमंत्री ने किया ई-विधान दिशा निर्देश विवरणिका और ई-विधान एप्प का शुभारम्भ

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने ई-विधान दिशानिर्देश विवरणिका (ब्रोशर) जारी करने के अतिरिक्त हिमाचल प्रदेश विधानसभा के ई-विधान एप्लीकेशन का भी शुभारम्भ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य विधानसभा का यह प्रयास प्रशंसनीय

है, जिससे विधानसभा सत्र के दौरान वाहनों की अनावश्यक आवाजाही रोक सुनिश्चित हो रही है तथा सरकार कागजों पर भारी खर्च की भी बचत कर रही है। उन्होंने कहा कि इस सुविधा से न केवल विधायी मामलों से सम्बद्ध जानकारी की समयबद्ध उपलब्धता सुनिश्चित हो रही है, बल्कि इससे राज्य के लोगों की बेहतर सेवा भी हो रही है

जय राम ठाकुर ने कहा कि राज्य विधानसभा को ई-विधान के लागू होने के बाद देश की पहली उच्च तकनीक वाली कागज रहित (पेपरलेस) विधानसभा होने का सौभाग्य प्राप्त है। उन्होंने कहा कि इसने न केवल कागजी उपयोग को कम किया है बल्कि सूचनाओं के तेजी से प्रसार के लिए ई-गवर्नेंस समाधानों का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित किया है। विधानसभा अध्यक्ष डा. राजीव बिंदल ने मुख्यमंत्री का स्वागत करते हुए कहा कि विधायकों को उनके निर्वाचन क्षेत्रों के प्रबंधन में ई-कांस्टीच्वेंसी प्रबंधन बहुत मददगार साबित हो रहा है। उन्होंने कहा कि अब जो बजट पेश किया जा रहा है वह इस ऐप के जरिए http://webcast-gov-in/hpvidhansabha पर ऑनलाइन उपलब्ध होगा। विधानसभा अध्यक्ष के निदेशक आईटी धर्मेश कुमार शर्मा ने ई-विधान सभा की प्रमुख विशेषताओं की जानकारी दी।

स्वाईन फ्लू पर आशा व स्वास्थ्य कार्यकर्ता गांव-गांव जाकर लोगों को करेंगी जागरूक:डॉ. दरोच

शिमला/शैल। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग सोलन द्वारा जिले में स्वाईन फ्लू को लेकर जागरूकता शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में क्षेत्रीय अस्पताल सोलन सहित चिकित्सा खण्ड अर्की, सायरी, नालागढ़, धर्मपुर तथा चण्डी में संबंधित खण्ड चिकित्सा अधिकारियों ने स्वास्थ्य पर्यवेक्षकों, स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं तथा आशा कार्यकर्ताओं के लिए शिविर आयोजित किए गए। यह जानकारी मुख्य चिकित्सा अधिकारी सोलन डॉ. आरके दरोच ने दी।

मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने कहा कि तथा इन शिविरों में स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं तथा आशा कार्यकर्ताओं को गांव-गांव जाकर लोगों को स्वाईन फ्लू के बारे में जागरूक करने बारे में जानकारी प्रदान की गई।

डॉ. दरोच ने कहा कि स्वाईन फ्लू का उपचार संभव है और यदि समय रहते रोगी अस्पताल या अन्य किसी स्वास्थ्य संस्थान में पहुंचता है तो उसका ईलाज किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि कसौली स्थित केंद्रीय अनुसंधान केंद्र, आईजीएमसी शिमला, डॉ. राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज टांडा तथा मंडी में स्वाईन फ्लू के परीक्षण की सुविधा उपलब्ध है।

जिला कार्यक्रम अधिकारी डॉ. एनके गुप्ता ने लोगों से आग्रह किया है कि वे बुखार, खांसी, सिरदर्द जैसे लक्षण दिखने पर समीप के स्वास्थ्य केंद्र में चिकित्सक से अवश्य परामर्श लें ताकि समय रहते रोग का निदान किया जा सके। उन्होंने कहा कि जिले सभी सिविल अस्पतालों, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों तथा क्षेत्रीय अस्पतालों में आइसोलेशन वार्ड बनाए गए हैं जहां पीड़ित रोगियों को अलग रखने की व्यवस्था होगी।

उन्होंने कहा कि बुखार, खांसी, सिरदर्द, गला दुखना, नाक बहना, बदन दर्द, थकान, सांस लेने में कठिनाई तथा उल्टियां व दस्त होने की स्थिति में चिकित्सक से परामर्श किया जाना जरूरी है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के विभिन्न भागों में स्वाईन फ्लू के मामलों के दृष्टिगत सोलन जिला में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा एहतियात के तौर पर सभी तैयारियां पूरी रखी गई हैं।

डॉ. एनके गुप्ता ने कहा कि स्वाईन फ्लू एक विशेष प्रकार के इन्फ्लुएंजा-ए (एच1 एन1) वायरस से फैलता है। यह बीमारी इस वायरस से ग्रसित व्यक्ति से संपर्क में आने पर भी हो सकती है। उन्होंने कहा कि स्वाईन फ्लू से उपचार व बचाव संभव है और रोगी को उपरोक्त लक्षण दिखने पर तुरंत चिकित्सक से परामर्श लेना चाहिए।

उन्होंने सलाह दी कि विभिन्न लक्षण होने पर रोगी अच्छी नींद लें, शारीरिक रूप से सक्रिय रहें तथा तनाव से बचें। उन्होंने कहा कि स्वच्छ तथा अधिक मात्रा में पानी पीएं तथा पोषणयुक्त आहार लें। उन्होंने प्रभावित माताओं को परामर्श दिया कि वे शिशुओं को दूध पिलाते समय अपना मुंह मास्क से ढक कर रखें।

उन्होंने कहा कि संक्रमित व्यक्तियों से न तो हाथ मिलाएं, न गले मिलें और न ही किसी अन्य प्रकार का संपर्क बढ़ाएं। उन्होंने कहा कि चिकित्सक के परामर्श के बिना कोई दवा न लें। बच्चों, गर्भवती महिलाओं, बुजुर्गों, मधुमेह एवं दमे से पीड़ित रोगियों को स्वाईन फ्लू होने का खतरा अधिक रहता है।

उन्होंने लोगों से आग्रह किया है कि स्वाईन फ्लू से भयभीत न हों और अपने समीप के स्वास्थ्य केंद्र में आवश्यकता पड़ने पर तुरंत परामर्श लें ताकि संभावित रोगी को उपचार देकर ठीक किया जा सके।

पटवारी के पदों के लिए 20 फरवरी तक करें आवेदन:उपायुक्त

शिमला/शैल। उपायुक्त कांगड़ा संदीप कुमार ने कहा कि जिले में पटवारियों के 42 रिक्त पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। उन्होंने कहा कि यह पद पुन: रोजगार के रूप में भरे जा रहे हैं, तथा इनके लिए सेवानिवृत कानूनगो एवं पटवारियों से आवेदन मांगे गए हैं। उन्होंने बताया कि पुन: नियुक्ति चयनित कानूनगो को 10 हजार रुपये जबकि पटवारी को 7810 रुपये प्रतिमाह दिया जाना प्रस्तावित है।

उन्होंने बताया कि इच्छुक सेवानिवृत कानूनगो या पटवारी जिनकी आयु 65 वर्ष से कम हो और जिनके विरूद्ध सतर्कता या विभागीय कार्यवाही लम्बित न हो वे 20 फरवरी, 2019 से पूर्व उपायुक्त कार्यालय कांगड़ा स्थित धर्मशाला में अपना आवेदन कर सकते हैं।

शैल समाचार
संपादक मण्डल
संपादक - बलदेव शर्मा
सयुक्त संपादक - जे.पी.भारद्वाज
विधि सलाहकार - ऋचा
अन्य सहयोगी
भारती शर्मा
रजनीश शर्मा
राजेश ठाकुर
सुदर्शन अवस्थी
सुरेन्द्र ठाकुर
रीना

HIMACHAL PRADESH
PUBLIC WORKS DEPARTMENT
E-Procurement Notice
INVITATION FOR BIDS (IFB)

1. The Executive Engineer HPPWD Chopal Distt. Shimla H.P. on behalf of Governor of H.P invites the online bids on item rate, in electronic tendering system, in 2 Cover System for the under mentioned work from the eligible and approved contractors/Firms registered with HPPWD Department.

Sr.No.	Name of Work	Estimated Cost	EMD	Cost of Tender	Eligibility class of Contractor
1.	R/R damages on Peontra Dawada to Titrod, Kimachandrauli road (SH: C/o B/wall between km. R.D. 0/660 to 0/680).	Rs.482000/-	Rs.10000/-	Rs.500/-	"D&C" Class
2.	C/o Bhoot Kainchi to Mundochali road km. R.D. 0/0 to 3/200 (SH: C/o HPC at km. 1/0, 1/45, B/wall in between km. R.D. 0/915 to 0/965 and R/wall in between km. R.D. 1/050 to 1/070).	Rs.1175000/-	Rs.24000/-	Rs.500/-	"D&C" Class
3.	C/o Mashrain to Bharan road km. 0/0 to 4/0 (SH: Laying of bearing coat GI in between km. R.D. 0/0 to 1/0.	Rs.259327/-	Rs.6000/-	Rs.500/-	"D&C" Class
4.	C/o Kiarna Ghat to Kanda road km. 0/0 to 1/195 under MMGPY (Cutting in earth work in between km. R.D. 0/0 to 0/315).	Rs.589747/-	Rs.10000/-	Rs.500/-	"D&C" Class
5.	C/o Painda to Kufer road km. 0/0 to 1/0 (SH: Formation cutting between km. 0/0 to 0/500 and C/o R/wall in between km. R.D. 0/020 to 0/045).	Rs.974681/-	Rs.10000/-	Rs.500/-	"D&C" Class
6.	C/o link road from Khula Batada to Sadona road km. 0/0 to 1/795 (SH: Formation cutting in between km. R.D. 0/0 to 1/0).	Rs.1518735/-	Rs.31000/-	Rs.500/-	"D&C" Class
7.	C/o link road to village Chhachhar and Pashar km. .0/0 to 4/500 under SSCP (SH: C/o 900mm dia HPC at R.D. 0/075, 3/705 and B/wall in between km. R.D. 1/625 to 1/645, 3/675 to 3/695).	Rs.410277/-	Rs.8500/-	Rs.500/-	"D&C" Class

2. Availability of Bid Document and mode of submission: The Bid document is available online and bid should be submitted in online mode on website **https://hptenders.gov.in.** Bidder would be required to register in the web-site which is free of cost. For submission of bids, the bidder is required to have Digital Signature Certificate (DSC) from one of the authorized Certifying Authorities (CA). **"Aspiring bidders who have not obtained the user ID and password for participating in e-tendering in HPPWD** may obtain the same from the website: **https://hptenders.gov.in.** Digital signature is mandatory to participate in the e-tendering. Bidders already possessing the digital signature issued from authorized CAs can use the same in this tender.

3. Key Dates:

1. Date of Online Publication	14.02.2019 10:00 HRS
2. Document Download Start and End Date	14.02.2019 1030 HRS up to 02.03.2019 1050 HRS
3. Bid Submission Start and End Date	14.02.2019 1030 HRS up to 02.03.2019 1050 HRS
4. Physical Submission of EMD and Cost of Tender Document	03.03.2019 up to 1030 HRS
5. Date of Technical Bid opening, Evaluation of Technical Bid followed by Opening of Financial Bid.	04.03.2019 1100 HRS

4. TENDER DETAILS:
The Tender Documents shall be uploaded online in 2 Cover:
i) Cover 1: shall contain scanned copies of all **"Technical Documents/ Eligibility**
ii) Cover2: shall contain **"BOQ/Financial Bid",** where contractor will quote his offer for each item.
5. SUBMISSION OF ORIGINAL DOCUMENTS: The bidders are required to submit (a) original demand draft towards the cost of bid document and (b) original bid security/Earnest Money Deposit (EMD) and other Technical Documents in **O/o Executive Engineer HPPWD Chopal H.P.** as specified in Key dates Sr. No. 4 on Tender Opening Date, failing which the bids will be declared non-responsive.
6. BID OPENING DETAILS: The bids shall be opened on **04.03.2019 at 1100 HRS** in the office **Executive Engineer, HPPWD Division Chopal H.P.** by the authorised officer. In their interest the tenderer are advised to be present along with original documents at the time of opening of tenders. If the office happens to be closed on the date of opening of the bids as specified, the bids will be opened on the next working day at the same time and venue.
7. The bids for the work shall remain valid for acceptance for a period not less than **90 days** after the deadline date for bid submission.
8. Other details can be seen in the bidding documents. The officer inviting tender shall not be held liable for any delays due to system failure beyond its control. Even though the system will attempt to notify the bidders of any bid updates, the Employer shall not be liable for any information not received by the bidder. It is the bidders' responsibility to verify the website for the latest information related to the tender.

Adv. No.-4578/18-19 **HIM SUCHANA AVAM JAN SAMPARK**

HIMACHAL PRADESH
PUBLIC WORKS DEPARTMENT
E-Procurement Notice
INVITATION FOR BIDS (IFB)

The **Executive Engineer, Mandi Division No. I, HPPWD, Mandi,** Distt Mandi H.P on behalf of Governor of H.P invites the online bids on item rate, in electronic tendering system, in 2 Cover System for the under mentioned work from the eligible and approved contractors/Firms registered with HPPWD Department.

Sr.No.	Name of Work	Estimated Cost (in Rs.)	EMD (in Rs.)	Cost of Tender (in Rs.)	Time of Compl-etion	Eligibility class of contra-ctor
1.	Construction of Ropa Khad Harizan Basti Ropru to Nasloh road Km. 0/0 to 3/500. (SH: C/O. Jeep able road from Km. 1/600 to 3/500).	12,75,749/-	25,600/-	500/-	Three Months.	"D"&"C"
2.	Construction of boundary wall around the College campus at Govt. Degree College Drang at Narla Tehsil Padhar District Mandi (HP). (SH: C/O. balance work of boundary wall except gate).	8,04,739/-	16,100/-	350/-	Three Months.	"D"&"C"

2. Availability of Bid Document and mode of submission: The Bid document is available online and bid should be submitted in online mode on website https://**hptenders.gov.in.** Bidder would be required to register in the web-site which is free of cost. For submission of bids, the bidder is required to have Digital Signature Certificate (DSC) from one of the authorized Certifying Authorities (CA). "Aspiring bidders who have not obtained the user ID and password for participating in e-tendering in HPPWD may obtain the same from the website: https://**hptenders.gov.in.** Digital signature is mandatory to participate in the e-tendering. Bidders already possessing the digital signature issued from authorized CAs can use the same in this tender.

3. Key Dates:

1. Date of Online Publication	08.02.2019 1700 HRS
2. Document Download Start and End Date	08.02.2019 1700 HRS upto 28.02.2019 1030 HRS
3. Bid Submission Start and End Date	08.02.2019 1700 HRS upto 28.02.2019 1030 HRS
4. Physical Submission of EMD and Cost of Tender Document	28.02.2019 upto 1030 HRS
5. Date of Technical Bid opening, Evaluation of Technical Bid followed by Opening of Financial Bid.	28.02.2019 1130 HRS

4. TENDER DETAILS:
The Tender Documents shall be uploaded online in 2 Cover:
i) Cover 1: shall contain scanned copies of all **"Technical Documents/ Eligibility Information".**
ii) Cover 2: shall contain **"BOQ/Financial Bid",** where contractor will quote his offer for each item.
5. SUBMISSION OF ORIGINAL DOCUMENTS: The bidders are required to submit (a) original demand draft towards the cost of bid document and (b) original bid security/Earnest Money Deposit (EMD) and other Technical Documents in **O/O Executive Engineer, Mandi Division No. I, HPPWD Mandi,** Distt Mandi (H.P) a payable at Mandi as specified in Key dates Sr. No. 4 on Tender Opening Date, failing which the bids will be declared non-responsive.
6. BID OPENING DETAILS: The bids shall be opened on **28.02.2019 at 11.30 HRS** in the office of **Executive Engineer, Mandi Division No. I, HPPWD Mandi,** Distt Mandi H.P by the authorised officer. In their interest the renderers are advised to be present along with original documents at the time of opening of tenders. If the office happens to be closed on the date of opening of the bids as specified, the bids will be opened on the next working day at the same time and venue.
7. The bids for the work shall remain valid for acceptance for a period not less than **120 days** after the deadline date for bid submission.
8. Other details can be seen in the bidding documents. The officer inviting tender shall not be held liable for any delays due to system failure beyond its control. Even though the system will attempt to notify the bidders of any bid updates, the Employer shall not be liable for any information not received by the bidder. It is the bidders' responsibility to verify the website for the latest information related to the tender.

Adv. No.-4527/18-19 **HIM SUCHANA AVAM JAN SAMPARK**

मुख्यमंत्री ने बैजनाथ पपरोला-पठानकोट के बीच एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने कांगड़ा जिले के बैजनाथ पपरोला रेलवे स्टेशन से बैजनाथ पपरोला से पठानकोट के बीच नई एक्सप्रेस ट्रेन नंबर 52476 को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।

मुख्यमंत्री ने 1 दिसंबर, 2018 को शिमला में एक बैठक के दौरान केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल के साथ पठानकोट- जोगिंद्रनगर और कालका-शिमला रेलवे पटरियों पर गाड़ियों की गति बढ़ाने के मुद्दे को उठाया था।

इस अवसर पर जनसभा को संबोधित करते हुए, मुख्यमंत्री ने कहा कि यह एक्सप्रेस सेवा न केवल स्थानीय जनता की तेजी से आवाजाही में मदद करेगी, बल्कि पर्यटकों को भी इस क्षेत्र में जाने के लिए प्रोत्साहित करेगी। उन्होंने कहा कि अब एक्सप्रेस ट्रेन 5 घंटे 5 मिनट में बैजनाथ पपरोला और पठानकोट के बीच की दूरी तय करेगी, जबकि पहले इस दूरी को तय करने में लगभग 7.15 घंटे का समय लगता था। उन्होंने कहा कि इससे ट्रेन की यात्रा और अधिक आकर्षक और सुखद होगी।

जय राम ठाकुर ने कहा कि यह रेलवे ट्रैक 1929 में अस्तित्व में आया था और लगभग 90 वर्षों के बाद पठानकोट और बैजनाथ के बीच का समय लगभग ढाई घंटे कम कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि इस ट्रैक पर बड़ी रेल को पटरी पर चलाने के प्रयास किए जाएंगे और ट्रैक के उन्नयन के संबंध में केंद्रीय रेल मंत्रालय से बात की जाएगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि फिरोजपुर रेलवे मण्डल ने चार कोच एक्सप्रेस ट्रेन बनाई है जिसमें एक प्रथम श्रेणी की चेयर कार, दो सामान्य सेवा कोच और एक सामान्य-गार्ड वैन शामिल हैं। उन्होंने कहा कि इस ट्रेन का पालमपुर, नगरोटा, कांगड़ा और ज्वालामुखी मार्ग पर ठहराव होगा।

जय राम ठाकुर ने कहा कि यात्रियों की सुविधा के लिए सभी प्रमुख

स्टेशनों पर वाईफाई सुविधा प्रदान की गई है। उन्होंने कहा कि कांगड़ा स्टेशन को हेरिटेज लुक प्रदान करने के लिए परामर्श कार्य सौंप दिया गया है, जिसे 10 मार्च, 2019 तक पूरा कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा पालमपुर-बैजनाथ के बीच बच्चों के लिए स्टीम रन पूरा किया गया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पालमपुर स्थित हेरिटेज गैलरी को नया रूप प्रदान करने व अन्य विभिन्न कार्य जैसे मुख्य स्टेशनों पर हेरिटेज वस्तुओं का प्रदर्शन, हेरिटेज प्रकाश स्तम्भ (लाइट पोल का उपयोग), दीवार घड़ियां, बेंच आदि का प्रदर्शन रेलवे द्वारा अधिक से अधिक पर्यटकों व आम लोगों को आकर्षित करने के लिए किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यात्रियों की सुविधा के लिए कांगड़ा घाटी रेलवे की वेबसाइट भी जल्द ही शुरू की जाएगी।

मुख्यमंत्री ने पपरोला होली मेले को जिला स्तरीय दर्जा तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र चढ़ियार को 50 बिस्तरों वाले अस्पताल का दर्जा देने की घोषणा की।

विधायक मुल्ख राज प्रेमी ने मुख्यमंत्री का अपने गृह क्षेत्र में स्वागत किया। इस एक्सप्रेस ट्रेन को क्षेत्र से हरी झंडी दिखाने के लिए मुख्यमंत्री ने धन्यवाद दिया। उन्होंने क्षेत्र की विभिन्न विकासात्मक मांगों को भी विस्तार से बताया।

इस अवसर पर मंडल रेल प्रबंधक विवेक कुमार ने मुख्यमंत्री और अन्य उपस्थित गणमान्य व्यक्तियों का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि इस एक्सप्रेस ट्रेन से क्षेत्र में पर्यटन विकास को एक नई गति मिलेगी। उन्होंने कहा कि इस खंड पर चलने वाली सभी ट्रेनों का नवीकरण किया गया है ताकि पर्यटक इस क्षेत्र की प्राकृतिक सुंदरता का आनंद ले सकें। उन्होंने कहा कि पालमपुर स्टेशन पर हेरिटेज गैलरी का निर्माण किया गया है। उन्होंने कहा कि पर्यटकों के आकर्षण के लिए पालमपुर और बैजनाथ के बीच भाप (स्टीम) हेरिटेज ट्रेन भी चलाई जा रही है। उन्होंने कहा कि कुल 26 मुख्य स्टेशनों में से पठानकोट और जोगिंद्रनगर खंड के बीच सभी 15 स्टेशनों को मुफ्त वाईफाई सुविधा प्रदान की गई है।

फोटोयुक्त मतदाता सूचियों का अंतिम प्रारूप पुनरीक्षण के लिए उपलब्ध

शिमला/शैल। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त कांगड़ा संदीप कुमार ने जानकारी दी है कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार 1 जनवरी, 2019 अहर्ता तिथि के आधार पर फोटोयुक्त सूचियां 21 जनवरी को जिला कांगड़ा के सभी 15 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में अन्तिम रूप से प्रकाशित की जा चुकी हैं। यह सूचियां सम्बन्धित निर्वाचक अधिकारियों के पास निरीक्षण हेतु उपलब्ध रहेंगी। उन्होंने बताया कि मतदाता सूचियों में सम्मिलित मतदाताओं का विवरण विभागीय बेवसाइट www.ceohimachal.nic.in पर भी उपलब्ध है।

उन्होंने बताया कि कोई भी मतदाता अपना या अपने परिवार के दर्ज नामों की उक्त बेवसाइट के माध्यम से पुष्टि कर सकता है। इसके अतिरिक्त मतदाता सूची में नाम दर्ज करने बारे जानकारी प्राप्त करने हेतु निर्वाचन विभाग के काल सैन्टर में निःशुल्क टेलीफोन सेवा (टोल फ्री नम्बर)1950 पर लैंडलाइन या मोबाइल फोन से सम्पर्क कर सकता है।

जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त ने बताया कि यदि किसी नागरिक का नाम फोटोयुक्त मतदाता सूचियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण-2019 के उपरांत दर्ज न हो सका हो और वह नागरिक 1 जनवरी, 2019 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका है या इससे अधिक आयु का हो, तो अभी भी वह निरंतर अद्यतन के अंतर्गत फार्म-6 भरकर सम्बंधित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (एसडीएम) के कार्यालय व सम्बंधित बूथ लेबल अधिकारी के द्वारा अपना नाम सम्मिलित करवा सकता है। किसी दर्ज नाम पर आपति दर्ज करने व मृत्यु या स्थान परिवर्तन के कारण फार्म-7 भरकर नाम हटाया जा सकता है। दर्ज नाम की प्रविष्टि या फोटो पहचान पत्र में शुद्धि हेतु फार्म-8 भरकर आवश्यक शुद्धि करवाई जा सकती है। नाम दर्ज, कटवाने व संशोधन करने की सुविधा निर्वाचन विभाग के आनलाईन पार्टल http//www.nvps.in/ पर भी उपलब्ध है।

उन्होंने समस्त नागरिकों, कर्मचारियों व राजनैतिक दलों से यह आह्वान किया है कि आगामी लोक सभा निर्वाचन के दृष्टिगत उक्त सुविधा का लाभ उठाएं। उन्होंने कहा कि पात्र नागरिक अपना नाम दर्ज करवायें व अपात्र व्यक्तियों जैसे मृतक, दोहरे पंजीकृत तथा स्थान त्याग चुके मतदाताओं के नाम हटाने की जानकारी बीएलओ व निर्वाचन विभाग को उपलब्ध करवाकर मतदाता सूचियों के अद्यतन करने में अपना महत्वपूर्ण सहयोग दें।

राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण ने बर्फ से प्रभावित जिलों के लिए की चेतावनी जारी

शिमला/शैल। सासे (मनाली) द्वारा चम्बा जिले के विभिन्न हिस्सों, लाहौल-स्पीति, शिमला, किन्नौर और कुल्लू में हिमस्खलन की चेतावनी के बाद हिमाचल प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (HPSDMA) ने विभागों और आम लोगों को चेतावनी जारी की है। सासे ने इन जिलों में हिमपात और हिमस्खलन की चेतावनी जारी की है।

राज्य सरकार के एक प्रवक्ता ने बताया कि जिला प्रशासन जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों (डीडीएमए) को सलाह दी गई है कि वे अपने क्षेत्रों में कड़ी निगरानी व एहतियात बरतें। उन्हें बचाव दलों को तैयार रखने और ऐसे स्थानों पर जहां हिमस्खलन की चेतावनी जारी की गई है, ऐसे स्थानों पर जाने से बचने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने पर्यटकों और स्थानीय लोगों को बर्फीले क्षेत्रों में न जाने की सलाह देने को कहा गया है तथा सभी अधिकारियों और स्थानीय निवासियों को खराब मौसम की चेतावनी देने के लिए निर्देशित किया गया है।संबंधित विभागों से कहा गया है कि वे राष्ट्रीय राजमार्गों और अन्य सड़कों पर कड़ी निगरानी रखें और संभावित हिमस्खलन रास्तों पर या उनके आस-पास की असुरक्षित बस्तियों को खाली करने की योजना तैयार रखने के निर्देश दिए गए हैं। आम लोगों को आवश्यक वस्तुओं और आपातकालीन दवाओं का पर्याप्त स्टॉक रखने की सलाह दी गई है। उन्होंने कहा कि विभागों को राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र (एसईओसी)-1070 पर तथा sdma.hp/nic.in पर किसी भी स्थिति में ईमेल करने को कहा गया है।

सभी स्कूलों में होगा संगीत अध्यापक:सुरेश भारद्वाज

शिमला/शैल। शिक्षा, विधि एवं संसदीय मामले मंत्री सुरेश भारद्वाज देहरा के राधा कृष्ण मंदिर में श्रीमती कमलावती सूद मेमोरियल भजन प्रतियोगिता के समारोह में बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित रहे।

इस अवसर पर उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए शिक्षा मंत्री ने कहा कि गीत संगीत मनुष्य समाज की सुखद कलायें हैं और संगीत हमें शारीरिक, मानसिक और आत्मिक स्वास्थ्य प्रदान करता है। उन्होंने कहा कि संगीत एक तरह की स्वर साधना और प्राणायाम है जिससे शरीर एवं मस्तिष्क स्वस्थ रहता है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि हिमाचल सरकार सभी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारने का प्रयास कर रही है और शिक्षा विभाग में संगीत को भी प्राथमिकता दे रही है। उन्होंने कहा कि सरकार ने निर्णय लिया है कि स्कूलों में संगीत की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए हर विद्यालय में संगीत का अध्यापक होगा। उन्होंने कहा कि आज प्रतिस्पर्धा का समय है और विद्यार्थी संगीत में भी अपना भविष्य बना सकते हैं जो कि उनके लिए रोजगार का साधन भी बन सकता है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि प्रदेश को केंद्र सरकार से सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत 830 करोड़ रुपये स्वीकृत हुये हैं। सरकारी स्कूलों में बच्चों की संख्या को बढ़ाने और उन्हें उच्च गुणवत्ता की शिक्षा के लिये प्रदेश में 3 हजार स्कूलों में नर्सरी की कक्षाएं शुरू की जा रही हैं। पहले प्रदेश में एक वर्ष में 20 स्कूलों में ही आईसीटी लैब की सुविधा दे पाते थे जबकि अब 125 स्कूलों को यह सुविधा मिलेगी। उन्होंने कहा कि अब प्रदेश के हर स्कूल में लाइब्रेरी की सुविधा भी दी

जाएगी। उन्होंने कहा कि हर स्कूल में पुस्तकालय हो, खेल का मैदान हो और बच्चों की पढ़ाई के लिये अच्छे क्लास रूम हों ताकि बच्चे अच्छे शैक्षणिक माहौल में शिक्षा ग्रहण कर सकें। इस के लिये प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के नेतृत्व में समग्र प्रयास कर रही है।

शिक्षा मंत्री ने कहा कि सरकार ने केंद्रीय विश्वविद्यालय खोलने के लिये सभी औपचारिकताएं पूरी कर ली हैं और शिक्षा का अगला सत्र शुरू होने से पहले सीयू का शिलान्यास कर दिया जाएगा। बजट बारे बोलते हुये उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने इस बजट में सभी की जरूरतों का ख्याल रखा है और इस से सभी वर्गों में खुशहाली आएगी।

समारोह में सेवानिवृत्त न्यायधीश अरुण गोयल व सुरेंद्र सूद ने अपने अन्य सदस्यों के साथ शिक्षा मंत्री का स्वागत किया और शिक्षा मंत्री को स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। समारोह में विभिन्न विद्यालयों और शिक्षण संस्थानों के बच्चों ने संगीत प्रतियोगिता में भाग लिया। शिक्षा मंत्री ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रतिभागियों को पारितोषिक वितरित किये।उन्होंने संस्था में सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिये अपनी ऐच्छिक निधि से 31 हजार रुपये देने की घोषणा भी की।

बजट गांव के विकास में अपनी अहम भूमिका अदा करेगा:विनोद

शिमला/शैल। हि.प्र. अराजपत्रित कर्मचारी सेवायें महासंघ ने जयराम सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट को विकासनोन्मुखी बताते हुए कहा है कि प्रदेश के सीमित वित्तीय संसाधनों के बावजूद मुख्यमन्त्री एवं वित मन्त्री जयराम ठाकुर द्वारा संतुलित और सभी वर्गो के हितों को ध्यान में रखते हुए पेश किया है, जिसका महासंघ स्वागत करता है। विनोद कुमार ने कहा है कि कर्मचारियों की आर्थिक मांगों पर ध्यान केन्द्रित करने के साथ-साथ यह बजट प्रदेश के ग्रामीण विकास में अपनी अहम भूमिका अदा करेगा बशर्ते बजट को कार्यान्वित करने वाले जो व्यवस्था का हिस्सा है, वे ईमानदारी, पारदर्शिता और इस बजट के हर लाभ को हर लाभार्थी तक एक तय समय सीमा के भीतर कार्यान्वयन करने का काम करेंगे। बजट के प्रस्तुतिकरण पर मुख्यमन्त्री जयराम ठाकुर की नीति और नियत काफी स्पष्ट झलकी है कि वे प्रदेश के वित्तीय सीमित संसाधनों के बावजूद प्रदेश सरकार की जनमानस के प्रति जिम्मेदारी निर्वहन करने में तत्पर है। इस बजट को जैसा कि मुख्यमन्त्री ने भी कहा है कि हिमाचल गावों में बसता है, इसी के चलते गांव के विकास को लेकर काफी फोकस किया गया है। जो कर्मचारियों की कुछ मागें इस बजट में रह गई हैं, वे आने वाले समय में समय रहते सरकार इस पर विचार करेगी । पूर्व कांग्रेस सरकार के समय प्रस्तुत बजटों में कभी भी इस प्रकार की एक समान नीति नज़र नहीं आई जो जयराम ठाकुर के बजट में काफी स्पष्ट है ।

यदि स्वयं में विश्वास करना और अधिक विस्तार से पढाया और अभ्यास कराया गया होता, तो मुझे यकीन है कि बुराइयों और दुःख का एक बहुत बड़ा हिस्सा गायब हो गया होता। स्वामी विवेकानंद

सम्पादकीय

मोदी–ममता की जीत में चिट फण्ड का पीड़ित हारा

क्या देश सत्ता की राजनीति के आगे हारता जा रहा है? क्या सत्ता ही एक मात्र सरोकार रह गया है? क्या सत्ता के आगे सबकुछ बौना पड़ गया है? आज यह सवाल शायद हर संवेदनशील व्यक्ति के ज़हन में उठ रहे हैं। क्योंकि पिछले दिनों जो कुछ मोदी और ममता के बीच घटा उससे यही सवाल तो उभरकर सामने आते हैं। 2014 में जब केन्द्र में सत्ता परिवर्तन हुआ था तब पूरा चुनावी परिदृश्य भ्रष्टाचार के गिर्द घूम गया था। अन्ना का लोकपाल के लिये आन्दोलन इसका सबसे बड़ा गवाह है। आज जब फिर लोकसभा के चुनाव सामने हैं और फिर सत्ता का फैसला होने जा रहा है तब फिर वही सबकुछ अपने को दोहराता नज़र आ रहा है। भ्रष्टाचार जहां 2014 में खड़ा था आज 2019 में भी वहीं खड़ा है। भ्रष्टाचार के जो मुद्दे उस समय खड़े थे उन पर पांच वर्षो के कार्यकाल में कुछ भी आगे नहीं बढ़ा है। अन्ना को फिर अनशन पर बैठना पड़ा। लेकिन इस बार अन्ना ने यह अवश्य स्वीकारा है कि 2014 में मोदी और केजरीवाल ने उनका इस्तेमाल किया था। परन्तु इस अनुभव के बाद भी अन्ना यह नहीं बता पाये कि वह इन चुनावों मे किसका समर्थन करेंगे। यह चुप्पी अन्ना की ईमानदारी है या विवशता इसका फैसला पाठकों को स्वयं करना होगा।

भ्रष्टाचार आज व्यवस्था की सबसे बड़ी बीमारी है और सभी इससे सहमत भी हैं। 1975 के आपातकाल के बाद हुए हर चुनाव में भ्रष्टाचार मुद्दा रहा है। भ्रष्टाचार कतई बर्दाश्त नही होगा और भ्रष्टाचारी को कड़ी से कड़ी सज़ा दी जायेगी यह वायदे भी हर चुनाव में मिले हैं। भ्रष्टाचार के खिलाफ जांच आयोग भी बैठे लेकिन क्या कोई ठोस परिणाम सामने आया है शायद नही। हां इस दौरान राज्यों में लोकायुक्त अवश्य स्थापित हुए हैं लेकिन क्या लोकायुक्त भी कोई स्मरणीय परिणाम दे पाये हैं? शायद इसका जबाव भी नहीं ही है। ऐसे में जब लोकायुक्त परिणाम नही दे पाये हैं तो लोकपाल क्या परिणाम देंगे इसका अन्दाजा लगाया जा सकता है। भ्रष्टाचार पर देश की सबसे बड़ी जांच ऐजेन्सी सीबीआई के शीर्ष अधिकारियों ने एक दूसरे के खिलाफ भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाये हैं यह देश देख चुका है। सीबीआई सीधे प्रधानमन्त्री के नियन्त्रण में है और पीएमओ इन अधिकारियों के झगड़े पर तब तक खामोश बैठा रहा जब तक की एफआईआर दर्ज होने और उच्च न्यायालय तक जाने की नौबत नही आ गयी। इसके बाद जो कुछ सरकार ने किया सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार की इस कारवाई को गलत करार दिया। लेकिन उसी सर्वोच्च न्यायालय का जब राफेल पर फैसला आया और उस फैसले पर अभी प्रतिक्रियाओं में जब सरकार पर शीर्ष अदालत में गलत ब्यानी का आरोप लगा तब सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय को यह कह दिया कि अदालत ने सरकार के जवाब में प्रयुक्त व्याकरण और भाषा को सही से नही समझा है। सरकार ने शीर्ष अदालत में यह सबकुछ लिखकर दिया है और आग्रह किया है कि इसे सुधार लिया जाये। लेकिन अभी तक शीर्ष अदालत ने सरकार के इस आग्रह पर आगे कुछ नही किया है। इस कुछ न करने से यह कहना कठिन है कि कौन सही है।

इसी तरह बंगाल में घटा चिटफण्ड घोटाला तो हुआ है। जनता के हजारों करोड़ों इसमें डूबे हैं। इतने बड़े घोटाले के पीछ किसी का राजनीतिक और प्रशासनिक आशीर्वाद न रहा यह विश्वास करना भी कठिन है लेकिन आज यह मामला किस तरह राजनीति की भेंट चढ़ रहा है यह देश के सामने आ गया है। जब इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने राजीव कुमार की गिरफ्तारी पर रोक लगाते हुए उसे सीबीआई के पास पेश होने के निर्देश दिये तो इसे ममता और मोदी दोनों ने अपनी जीत करार दिया। जब दोनों की ही जीत हुई है तो निश्चित रूप से इसमें हर वह आदमी हारा है जिसका पैसा इस घोटाले में डूबा है। क्योंकि अब घोटाले से पहले यह जांच होगी कि इसमें सीबीआई सही था या राजीव कुमार। इसमें अब राजनीति के लिये दोनो पक्षों को खुला मैदान मिल गया है। क्योंकि इसी मामले में जिस टीएमसी सांसद मुकुल कुमार से सीबीआई पूछताछ कर चुकी है वह अब भाजपा में शामिल हो चुका है। यही नही वह आईएस अधिकारी भारती घोष जिसके यहां छापेमारी में 2.5 करोड़ की रिकवरी हुई थी वह भी भाजपा में शामिल हो चुकी है। इसी के साथ सीबीआई के जिस निदेशक नागेश्वर राव के निर्देशों पर ऐजैन्सी के चालीस लोगों की टीम राजीव कुमार के यहां छापेमारी के लिये गयी थी उसकी पत्नी और बेटी के खिलाफ बंगाल में चल रही जांच का प्रकरण भी सामने आ गया है। इस तरह एक दूसरे के खिलाफ राजनीतिक फायरिंग करने के लिये काफी बारूद इकट्ठा हो गया है। इस पर अब खुलकर इन चुनावों तक राजनीति होगी और चिटफण्ड घोटाला अगले चुनावों तक ऐसे ही धीरे–धीरे सुलगता रहेगा। यही सबकुछ अखिलेश, माया, हुड्डा और वाड्रा के मामलों का सच है। हर चुनाव से पहले उठेंगे और फिर शांत हो जायेंगे। 1984 के दंगो में अब सज़ा की बारी आयी है इसी तरह संभव है कि गुजरात दंगा के दोषीयों की बारी भी चालीस साल बाद आ जाये क्योंकि हत्यायें तो वहां भी हुई हैं।

यह सब एक भयानक सच है कि आज देश के राजनीतिक नेतृत्व को अपराध और भ्रष्टाचार से राजनीति से हटकर कोई सरोकार नही रह गया है। न्यापालिका भी अब इसमें बराबर की भागीदार बनती जा रही है क्योंकि दशकों तक लोकहित के मामले लंबित रखे जा रहे हैं। जांच ऐजैन्सीयों की जिम्मेदारी अदालतें अपने फैसलों में तो लगा देती हैं लेकिन उसके बाद उन निर्देशों /आदेशों पर कितना अमल हुआ है यह जानने का प्रयास ही नही किया जाता। क्योंकि सामाजिक सरोकारों के लिये कोई भी गंभीर और संवेदनशील नही रह गया है। हर अपराध और भ्रष्टाचार को सत्ता की सीढी बनाकर इस्तेमाल किया जा रहा है। सत्ता के लिये सारी स्थापित रिवायतों को तोड़ा जा रहा है और फिर उसे जायज़ भी ठहराया जा रहा है। इस पर सवाल उठाने वाले को आसानी से वैचारिक विरोधी करार दे दिया जाता है। आज सत्ता इस राजनीति के आगे तो शायद राम भी हारते जा रहे हैं। क्योंकि जब मन्दिर निर्माण के लिये साधुओं ने कूच कर दिया है तो वहां पर होने वाली कानून और व्यवस्था की जिम्मेदारी किसी भी संगठन को लेने की आवश्यकता ही नही रह जाती है। इसी परिदृश्य में तो वीएचपी ने चार माह के लिये अपना आन्दोलन स्थगित किया है। राजनीति की इस पराकाष्ठा के बाद शायद यही कहना पड़ेगा कि आज की राजनीति के आगे सिर्फ देश हार रहा है।

पश्चिम बंगाल में जो भी हुआ वह भारत के संघीय बनावट पर आक्रमण है

'गौतम चौधरी'

केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो– सीबीआई के बीच का झगड़ा अभी शांत भी नहीं हुआ था कि देश की यह सबसे बड़ी जांच एजेंसी एक नए विवाद में फंस गयी है। दरअसल, कोलकाता के पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार से सीबीआई की टीम पूछताछ करने के लिए कोलकाता गयी थी। सीबीआई राजीव कुमार से पूछताछ करती, उससे पहले ही कोलकाता पुलिस ने उस टीम को थाने में बिठा लिया। मतलब टीम को बंगाल पुलिस ने अपने अभिरक्षण में ले लिया। यह देश की पहली घटना है जब किसी केन्द्रीय जांच एजेंसी की टीम को इस प्रकार राज्य पुलिस के द्वारा थाने में बिठाया गया हो। यह घटना देश की सम्प्रभुता को चुनौती देने वाली घटना से कम नहीं है। हालांकि इस घटना पर बंगाल की ममता बनर्जी की सरकार के पास अपने तर्क हैं और सीबीआई को नियंत्रित करने वाली केन्द्र सरकार के अपने तर्क हैं। निःसंदेह तर्क होंगे। मसलन हर घटना को नैतिक और कानूनी तौर पर वैध ठहराने के तर्क गढ लिए जाते हैं लेकिन जो हड़कत पश्चिम बंगाल की पुलिस ने की है वह भारतीय संघीय व्यवस्था पर चोट है और इसे किसी कीमत पर उचित नहीं ठहराया जा सकता है। यहां मैं कुछ उदाहरण देना चाहूंगा। मसलन पंजाब के खालिस्तानी चरमपंथी जरनैल सिंह भिंडरावाला को किसी समय में एक खास राजनीतिक दल की ओर से संरक्षण मिला था। आपको बता दें कि एक मामले को लेकर भिंडरावाले पर मुकदमा चलाया गया था लेकिन वह अदालत में जाने से इन्कार कर दिया और कहा कि मैं भारत के अदालत में विश्वास ही नहीं करता हूं। फिर उसकी सुनवाई गुरदर्शन प्रकाश गुरुद्वारा, मेहता चौक, जिला अमृतसर में हुआ। उसका प्रतिफल पूरा देश देख चुका है। प्रथम चरण में संरक्षण देने वाले राजनीतिक दल को भिंडरावाला से फायदा दिखा लेकिन बाद में वही भिंडरावाला देश की संप्रभुता के लिए खतरा पैदा किया और संरक्षण देने वाले का भी सर्वनाश कर दिया। इसी प्रकार सुभाष घिसिंग का मामला है। लालू यादव के मामले की चर्चा यहां करना मैं जरूरी समझता हूं। मामला बेहद रुचिकार है। कोर्ट के आदेश पर सीबीआई बिहार में चारा घोटाले की जांच कर रही थी। ज्वाइंट डायरेक्टर यूएन विश्वास, जांच टीम को लीड कर रहे थे। बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू प्रसाद के अनुरोध पर सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाईकोर्ट को जांच की निगरानी का जिम्मा सौंपा। सीबीआई ने जांच की प्रारंभिक रिपोर्ट कोर्ट में पेश की। सीलबंद रिपोर्ट पढ़ कर न्यायाधीश चौंक पड़े। उन्होंने डा. विश्वास से पूछा कि क्या यह आपकी रिपोर्ट है? विश्वास ने इंकार में सिर हिलाते हुए अपनी जेब से एक दूसरी रिपोर्ट निकालकर अदालत को दिया। कोर्ट में उपस्थित सभी हैरानी से यह देख रहे थे। जजों ने दूसरी रिपोर्ट भी पढ़ी फिर पूछा– दोनों रिपोर्ट में अंतर क्यों है? डॉ. विश्वास ने बताया की नियमानुसार उन्होंने अपनी रिपोर्ट सीबीआई निदेशक को भेजी थी। वहां से एडिट होकर रिपोर्ट कोर्ट में पहुंची है लेकिन उन्होंने अपनी रिपोर्ट की एक कॉपी रख ली थी, जो आपके पास है। सीबीआई के तत्कालीन डायरेक्टर जोगिंदर सिंह भी कोर्ट में मौजूद थे। उनका चेहरा स्याह पड चुका था। मूल रिपोर्ट में परिवर्तन क्यों किया गया, कोर्ट के इस सवाल का वे जवाब नहीं दे सके। जजों को मामला समझते देर नहीं लगी। कोर्ट ने तत्काल जोगिन्दर सिंह को चारा घोटाले जांच से अलग रहने का निर्देश दिया। विश्वास को स्वतंत्र रूप से मामले की जांच का आदेश हुआ। कहा गया कि वे अपनी रिपोर्ट सीधे कोर्ट को सौंपे। इसके बाद विश्वास की जांच जो शुरु हुई तो वह घोटालेबाजों को सलाखों के पीछे करके ही रुकी। 20 साल तक बिहार पर राज करने की घोषणा करने वाले लालू प्रसाद को 6 साल के बाद ही मुख्यमंत्री की गद्दी छोड़ जेल जाना पड़ा। विभिन्न दलों के आधे दर्जन से अधिक राजनेताओं और अफसरों को सजा हुई। यहां मैं एक बात यह भी बता दूं कि कालांतर में ममता बेनर्जी जितनी घातक तो नहीं लेकिन कुछ इसी प्रकार की परिपाटी भाजपा शासित प्रदेश के मुख्यमंत्रियों ने भी की है। 2012 में रमन सिंह के शासनकाल के दौरान सीबीआई के अधिकारियों को बंधक बना लिया गया था। 2012 में रमन सिंह के शासनकाल के दौरान सीबीआई के अधिकारियों को बंधक बना लिया गया था। मार्च, 2011 में छत्तीसगढ़ के बस्तर में ताड़मेटला कांड हुआ था। इस कांड में 300 घरों को आग लगा दी गई थी और तीन लोगों की हत्या कर दी गई थी। इस हत्याकांड के आरोप लगे थे छत्तीसगढ़ के विशेष सुरक्षा बलों पर, जिन्हें एसपीओ कहा जाता है। मामले की जांच सीबीआई कर रही थी। इस कांड की जांच के लिए सीबीआई के भोपाल जोन के 6 अधिकारी 9 फरवरी, 2012 की शाम को ताड़मेटला पहुंचे थे। उसी दिन सुकमा के एएसपी डीएस मरावी पर माओवादियों ने हमला कर दिया। इस दौरान एक एसपीओ करलम सूर्या की मौत हो गई। वहीं माओवादियों से बात करने पहुंचे स्वामी अग्निवेश पर भी हमला हुआ। कुल मिलाकर इलाके का माहौल बेहद खराब हो गया था। इसी माहौल में सीबीआई के अधिकारी ताड़मेटला कांड की जांच के लिए पहुंच गए थे।

सीबीआई के अधिकारियों को देखते एसपीओ भड़क गए और आरोप लगाया कि सीबीआई अधिकारी ही एसपीओ करलम सूर्या की मौत के जिम्मेदार हैं। इसके बाद सीबीआई के अधिकारियों ने खुद को एक रूम में बंद कर लिया। सीबीआई अधिकारियों ने आरोप लगाया कि एसपीओ के पास हथियार और हथगोले भी थे और उन्होंने फायरिंग भी की थी।

2012 में शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने एक आदेश पारित कर सीबीआई के खिलाफ मोर्चा खोला था। उस आदेश में केंद्रीय एजेंसियों को राज्य में ऑपरेशन से अलग कर दिया गया था। 12 अक्टूबर, 2012 को शिवराज सरकार के गृह विभाग ने एक नोटिफिकेशन जारी किया। उस नोटिफिकेशन में कहा गया था कि मध्यप्रदेश सरकार दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946 के तहत इस बात की इजाजत देती है कि केंद्र सरकार की जांच एजेंसी मध्यप्रदेश में जांच कर सकती है लेकिन वो जांच एजेंसियां मध्यप्रदेश सरकार के तहत आने वाले आईएएस, आईपीएस और आईएफएस अफसरों की जांच नहीं कर सकती है। इसका सीधा सा मतलब ये था कि कोई भी केंद्रीय एजेंसी मध्यप्रदेश के अधिकारियों को हाथ भी नहीं लगा सकती है। हालांकि पश्चिम बंगाल की सराकर ने अपने अधिकारी को संरक्षित करने के लिए ऐसा किया लेकिन इसके भी अन्जाम बुरे हो सकते हैं। वैसे इस मामले में केन्द्र की नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार की भी भूमिका बहुत अच्छी नहीं कही जा सकती है। वैधानिक रूप से सीबीआई राज्य सराकर की बिना अनुमति प्रदेश में किसी प्रकार का कोई अभियान नहीं चला सकती है। भारतीय संघीय ढंचे में राज्य को स्वायत्ता मिली हुई है। कई राज्य पहले से सीबीआई के प्रवेश को लेकर लिखित अनुमति केन्द्रीय गृह मंत्रालय को दे रखें है लेकिन कई राज्य सरकारें केस के आधार पर सीबीआई को अनुमति प्रदान करती है। इधर जब केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो में उठा–पटक प्रारंभ हुआ तो सीबीआई की विश्वसनीयता पर प्रश्न खड़ा करते हुए आंध्र प्रदेश की सराकर ने अपनी अनुमति वापस ले ली। फिर पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार ने भी इसकी घोषणा की और अब थोड़े दिन पहले छत्तीसगढ की सरकार ने भी ऐसा ही किया। ऐसे में यह मामला राजनीतिक रूप से संवेदनशील हो गया और इस मामले को केन्द्र सरकार को राजनीतिक हस्तक्षेप से ही संभालना चाहिए था लेकिन केन्द्र सरकार ने ऐसा कुछ भी नहीं किया उलटे सीबीआई की टीम पश्चिम बंगाल पहुंच गयी। इसे केन्द्र सरकार की नाकामी ही कहनी चाहिए। यदि समय रहते केन्द्र सरकार मामले में हस्तकक्षेप की होती तो आज ममता बनर्जी की सरकार को यह कदम उठाने की जरूरत नहीं पडती। हालांकि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय बेहद उचित और अनुभव वाला कहा जा सकता है। पुलिस अधिकारी राजीव कुमार से पूछताछ की अनुमति कोर्ट ने दे दी है। कोर्ट के इस निर्णय को केन्द्र सरकार और सीबीआई अपनी जीत बता रही है लेकिन जो संघीय ढंचे पर आक्रमण हुआ है उसके लिए न तो कोर्ट कुछ कहने के लिए तैयार है और न ही केन्द्र सरकार। कोर्ट ने सापफ–साफ कह दिया है कि विधायिका का मामला है इसलिए हम उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। यदि यही परिपाटी चली तो फिर हर प्रदेश अपने–अपने आंतरिक मुद्दों को ध्यान में रखकर संघीय ढांचों पर प्रहार करेगा। इस पर सत्ता प्रतिष्ठान को गंभीरता से सोचना चाहिए। भारत विभिन्न अनुशासन, सभ्यता, संस्कृति, भाषा, पंथ, जाति और धर्म का देश है। इस देश को एक बनाने में हमारे संविधान की महत्वपूर्ण भूमिका है। देश की एकता और अखंडता सर्वोपरी है। इसके खिलाफ किसी प्रकार के कृत्य अक्षम्य हैं। यह राष्ट्र तभी एकीकृत रह पाएगा जब हम अपने–अपने हद में रहेंगे अन्यथा हम बिखर जाएंगे। हमने चेकोसलोवाकिया, अफगानिस्तान, सीरिया मिस्र, वियतनाम, कोरिया आदि दुनिया के कई देशों को आधुनिक युग में पराभूत होते देखा है। सोवियत यूनियन भी इसी प्रकार के कुछ अंतर्विरोधों के कारण धराशाई हुआ। हमें वह भूल नहीं करनी चाहिए जो हम लगातार कर रहे हैं।

इस मामले में ममता बनर्जी को भी तसल्ली से काम लेना चाहिए हालांकि उनके आरोप ज्यादा तल्ख हैं लेकिन बातचीत से राजनीतिक समस्या का हल निकाला जा सकता था पर ऐसा नहीं हुआ। केन्द्र सरकार की ओर से बताया जा रहा है कि चीट–फंड घोटाले की जांच के लिए सीबीआई कोलकाता गयी थी लेकिन सीबीआई के अंतरिम निदेशक नागेश्वर राव की पत्नी की कंपनी का एंगल भी यहां फंस रहा है। फिर भाजपा ने चुनाव आयोग से राजीव कुमार पर आपत्ति दर्ज कराई थी। इधर ममता बनर्जी का आरोप है कि चीट–फंड घोटाले के मास्टर माइंड आज भाजपा के नेता बने हैं और उनके उपर सीबीआई जांच ढीली चल रही है लेकिन जो भाजपा में शामिल नहीं हुए उनके उपर जबरदस्त कार्रवाई हो रही है यह सरासर अन्याय है। आंतरिक बात क्या है यह तो जांच के बाद ही पता चलेगा लेकिन दोनों ओर से जिस प्रकार मामले पर पहल हुई वह तरीका बेहद गलत है और भारत के संघीय ढांचे पर आक्रमण है। इस प्रकार की गतिविधि से हर संवैधानिक इकाई को परहेज करना चाहिए।

2019 की चुनावी बिसात पर राहुल की व्यूह रचना

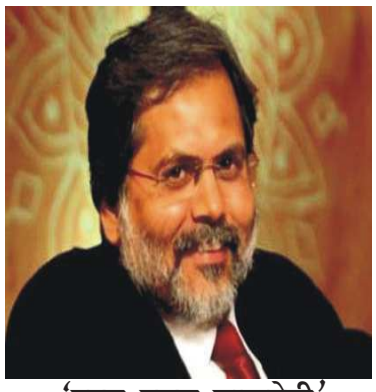

'पुण्य प्रसून बाजपेयी'

2019 की दौड में नरेन्द्र मोदी और राहुल गांधी अगुवाई कर रहे है तो अगुवाई करते नेता के पीछे खडे क्षत्रप की एक लंबी फौज है जो अपने अपने दायरे में खुद की राजनीतिक सौदेबाजी के दायरे को बढ़ा रहे हैं। इस कडी में ममता, मायावती, अखिलेश, चन्द्रबाबू, चन्द्रशेखर राव, कुमारस्वामी, तेजस्वी, हेमंत सोरेन, नवीन पटनायक सरीखे क्षत्रप हैं। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है वैसे वैसे तस्वीर साफ होती जा रही है कि राजनीतिक बिसात बनेगी कैसी। ध्यान दे तो नरेन्द्र मोदी की थ्योरी राष्ट्रवाद को लेकर रही है। इसलिये वह चार मुद्दो को उठा रहे हैं। पहला विदेशों में मोदी की वजह से भारत का डंका बज रहा है। दूसरा, डोकलाम में चीन को पहली बार मोदी की कूटनीति ने ही आईना दिखा दिया। तीसरा, सर्जिकल स्ट्राइक के जरीये पाकिस्तान को धूल चटा दी। और चौथा हिन्दुत्व के रास्ते सत्ता चल रही है। और इसके लिये वह नॉर्थइस्ट में बांग्लादेशियो को खदेडने के लिये कानून बनाने से भी नहीं चूक रही है। लेकिन राहुल गांधी की थ्योरी खुद को राष्ट्रवादी बताते हुये अब मोदी के राष्ट्रवाद की थ्योरी तले इक्नॉमी के अंधेरे को उभार रही है। राहुल गांधी का कहना है राष्ट्रवादी तो हम भी हैं और जहां तक हिन्दुत्व की बात है तो जनेउधारी तो हम भी हैं लेकिन दुनियाभर में डंका पिटने के बावजूद मोदी का राष्ट्रवादी गरीबों के लिये कुछ नही कर रहा है ये सिर्फ कारपोरेट हित साध रहा है। यानी 2019 की तरफ बढ़ते कदम मोदी की व्यूह रचना में राहुल की सेंध को ही इस तरह जगह दे रहे हैं जैसे एक वक्त की कांग्रेस की चादर अब बीजेपी ने ओढ़ ली है और गरीबों का जिक्र कर कांग्रेस में समाजवादी – वामपंथी सोच विकसित हो गई है। यानी 2019 की बनती तस्वीर में क्षत्रपों के सामने संकट पारम्परिक जाति और धर्म के मुद्दे के हाशिये पर जाने से उभर रहा है। यानी आर्थव्यवस्था को लेकर जिस तरह कांग्रेस सक्रिय हो चली है और राममंदिर को जिस तरह मोदी के साथ संघ परिवार ने भी चुनाव तक टाल दिया है उसमें जातिय समीकरण के आधार पर राजनीति करने वाले क्षत्रपों के सामने ये संकट है कि उनका वोट बैंक भी उस विकास को खोज रहा है जो उनके पेट और परिवार से जा जुड़ा है। इससे क्षत्रपों की सौदेबाजी भी खासी कमजोर हो चली है। यानी इस तस्वीर का पहला पाठ तो यही है बीजेपी क्षत्रपों को जीने नहीं देगी और कांग्रेस क्षत्रपों को अपनी शर्तो पर समझौता कराने की दिशा में ले जायेगी। राहुल प्रियंका की जोड़ी कांग्रेस में आक्सीजन भर रही है या फिर क्षत्रपों के सामने जीवन मरन का संकट खड़ा कर रही है। ये सवाल धीरे – धीरे इसलिये बड़ा होता जा रहा है क्योंकि कांग्रेस के कदम एकला चलो या फिर लोकसभा में ज्यादा से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़कर अपनी संख्या को बढाने के फार्मूले की तरफ बढ़ चुके हैं और ये सब कैसे हो रहा है ये देखना बेहद दिलचस्प है। क्योंकि राहुल और प्रियंका एक साथ जब चुनाव प्रचार के लिये उतरेंगे तो इसका मतलब साफ है कि यूपी बिहार झारखंड बंगाल, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा को लेकर साफ थ्योरी होगी कि क्षत्रपों को राज्यों में अगुवाई की बात कहकर लोकसभा चुनाव में ज्यादा से ज्यादा सीट पर खुद लड़े। और मोदी विरोध की थ्योरी के सामानातंर प. बंगाल, आंध्रप्रेदश और उडिसा में किसी भी क्षत्रप के साथ समझौता ना करें। इस थ्योरी को सिलसिलेवार समझें। यूपी में एक तरफ मायावती को लेकर मुस्लिम समेत जाटव छोड़ बाकि दलित जातियों में ये सवाल अब भी है कि क्या चुनाव के बाद मायावती सत्ता के लिये कहीं बीजेपी के साथ तो खडा नहीं हो जायेगी। तो दूसरी तरफ अखिलेश के सामने यादव वोट बैंक के अलावा ओबीसी जातियों के बिखराव का संकट भी है और मायावती के साथ गठबंधन के बावजूद दलित वोट का ट्रासंफर ना होने की स्थिति भी है। फिर कांग्रेस को लाभ सीधा है। पहला – कांग्रेस आर्थिक आधार पर अपने पारंपरिक वोट बैंक को जोड़ने उतरेगी। तो दूसरा महिला, युवा और अगड़ी जातियों के वोट को प्रियंका के आसरे जोड़ेगी। तो यूपी से सटे बिहार झारखंड में कांग्रेस अपनी सौदेबाजी के दायरे को बढ़ा रही है। इसलिये बिहार में तेजस्वी हो या झारखंड में सोरेन। दोनों के सामने कांग्रेस का प्रस्ताव साफ है – तेजस्वी – सोरेन सीएम बने लेकिन लोकसभा की सीट ज्यादा कांग्रेस के पास होगी। और ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने का फार्मूला ही प. बंगाल और आंध्रप्रदेश में कांग्रेस को गठबंधन के बोझ से मुक्त कर चुका है। इसलिये कांग्रेस ने बंगाल में ममता बेनर्जी के साथ तो आंध्र में चन्द्रबाबू के साथ मिलकर चुनाव ना लड़ने का फैसला किया है। यानी कांग्रेस इस हकीकत को बखूबी समझ रही है कि लोकसभा चुनाव में जिसके पास ज्यादा सीट होगी उसकी दावेदारी ही चुनाव के बाद पीएम के उम्मीदवार के तौर पर होगी और इसके लिये जरुरी है अपने बूते चुनाव लड़ना। तो ऐसे में प्रियंका की छवि कैसे नरेन्द्र मोदी की छवि को खत्म करेगी इस पर कांग्रेस का ध्यान है क्योंकि 2014 में नरेन्द्र मोदी जिस हंगामे और जिस तामझाम के साथ आये ये कोई कैसे भूल सकता है और तब प्रचार में बीजेपी कहीं नहीं थी सिर्फ मोदी थे। लेकिन इसके उलट प्रियंका गांधी की एंट्री बेहद खामोशी से हुई। कांग्रेस मुख्यालय में नेम प्लेट टांगने से लेकर कार्यकत्ताओं से बिना हंगामे मिलने के तौर तरीके ने ये तो साफ जतला दिया कि प्रिंयका को किसी प्रचार की जरुरत नहीं है और कांग्रेस का मतलब ही नेहरु गांधी परिवार है। लेकिन बीजेपी यहां भी अपने ही कटघरे में फंस गई। जब उसने खामोश प्रियंका को खानदान और बिना हंगामे के राजनीति तले सिर्फ परिवार के अक्स में देखना शुरु किया। यानी प्रियंका की छवि बीजेपी ने ही अपनी आलोचना से इतनी रहस्यमयी और जादुई बना दिया कि प्रियंका के बारे में जानने के लिये वोटरों में भी उत्सुकता जाग गई। और कांग्रेस ने प्रियंका की छवि को मुद्दो को आसरे जिस तरह उभारने की कोशिश शुरु की है वह ना सिर्फ प्रियंका को इन्दिरा गांधी से जोड़ रही है बल्कि इंदिरा के दौर में जिस तरह गरीबी हटाओ का नारा बुलंद हुआ और जिस तरह मोदी के कारपोरेट प्रेम तले किसान मजदूर का सवाल कांग्रेस उठा रही है उसमें चाहे अनचाहे 2019 का चुनाव अमीर बनाम गरीब की तरफ बढ़ता जा रहा है तो सवाल तीन है पहला, क्या प्रियंका को सिर्फ यूपी तक सीमित रखा जायेगा। दूसरा, क्या प्रिंयका को यूपी के सीएम के तौर पर प्रोजेक्ट भी किया जायेगा। तीसरा, क्या प्रियंका की छवि राहुल के लिये मुश्किल पैदा करेगी। पर इन सवालों का जवाब भी कांग्रेस के पास है। ध्यान से परखे तो प्रियंका गांधी को चुनावी मैदान में तब उतारा गया जब राहुल गांधी की छवि पप्पू से हट कर एक परिपक्व नेता के तौर पर बनने लगी। फिर राहुल गांधी ने अपनी राजनीति से मोदी को कारपोरेट के साथ खड़ा करने में राजनीतिक सफलता पायी और – तीसरा, किसान और बेरोजगारी के सवाल को जिस तरह राहुल ने मथा उसका ठीकरा मोदी सत्ता पर फूटा। और इसी अक्स में प्रियंका का राजनीतिक एन्ट्री ही राहुल गांधी ने इस स्ट्रेटजी के साथ किया कि इन्दिरा की छवि में गरीबों के सवाल को साथ लेकर अगर प्रियंका प्रचार मैदान में कूदेगी तो मोदी का ओहदा खत्म होगा।

राहुल की लड़ाई भ्रष्टाचार से है या मोदी से?

देश देख रहा है कि जिस प्रकार की संवेदनशीलता से वे रॉफेल सौदे में कथित भ्रष्टाचार को लेकर मोदी के खिलाफ दिखा रहे हैं, वो ममता के प्रति शारदा घोटाले, या अखिलेश के प्रति उत्तर प्रदेश के खनन घोटाले अथवा मायावती के प्रति मूर्ति घोटाले या फिर लालू और तेजस्वी के प्रति चारा घोटाले या चिदंबरम के प्रति आई एन एक्स के भ्रष्टाचार के मामलों में नहीं दिखा रहे।

– डॉ. नीलम महेंद्र –

क्या राहुल रॉफेल डील से सचमुच असंतुष्ट हैं? अगर हाँ, तो जैसा कि रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, उन्हें ठोस सबूत पेश करने चाहिए। अगर वो कहते हैं और मानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अनिल अंबानी को 30 हजार करोड़ रुपए दिए हैं तो इसे सिद्ध करें, कहीं न कहीं किसी ना किसी खाते में पैसों का लेनदेन दिखाएं। काश कि वो और उनके सलाहकार यह समझ पाते कि इस प्रकार आधी अधूरी जानकारियों के साथ आरोप लगाकर वे मोदी की छवि से ज्यादा नुकसान खुद अपनी और कांग्रेस की छवि को ही पहुँचा रहे हैं। क्योंकि देश देख रहा है कि जिस प्रकार की संवेदनशीलता से वे रॉफेल सौदे में कथित भ्रष्टाचार को लेकर मोदी के खिलाफ दिखा रहे हैं, वो ममता के प्रति शारदा घोटाले, या अखिलेश के प्रति उत्तर प्रदेश के खनन घोटाले अथवा मायावती के प्रति मूर्ति घोटाले या फिर लालू और तेजस्वी के प्रति चारा घोटाले या चिदंबरम के प्रति आई एन एक्स के भ्रष्टाचार के मामलों में नहीं दिखा रहे। देश देख रहा है कि इन मामलों में सुबूतों के आधार पर पूछताछ करने पर भी कांग्रेस कहती है कि मोदी सरकार विपक्ष को डराने का काम कर रही है लेकिन उच्चतम न्यायालय से क्लीन चिट मिलने के बाद भी रॉफेल को मुद्दा बनाने को कांग्रेस अपना अधिकार समझती है। यह खेद का विषय है कि राहुल रॉफेल को एनडीए का बोफोर्स सिद्ध करने की अपनी कोशिश में हैं, ताकि वे इसे लोकसभा चुनावों में एक अहम मुद्दा बनाकर अपना राजनैतिक स्वार्थ हासिल कर सकें। इस प्रकार वे देश को गुमराह करके देश की ऊर्जा और समय दोनों नष्ट कर रहे हैं।

राहुल गांधी ने रॉफेल को लेकर ताजा आरोप एक अंग्रेजी अखबार द हिन्दू में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की एक अधूरी चिट्ठी को आधार बनाकर लगाया। लेकिन हर बार की तरह यह आरोप भी तब ध्वस्त हो गया जब रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने पूरी चिट्ठी और उसका सच सामने रख दिया। लेकिन राहुल संतुष्ट नहीं हुए। हो भी कैसे सकते हैं? जब रॉफेल पर वो संसद में रक्षा मंत्री के जवाब से और सुप्रीम कोर्ट के फैसले से ही संतुष्ट नहीं हुए तो अब रक्षा मंत्री के ब्यान से संतुष्ट कैसे हो सकते हैं? ऐसा लगता है कि राहुल इस समय अविश्वास के एक अजीब दौर से गुजर रहे हैं। उन्हें प्रधानमंत्री पर विश्वास नहीं है, उन्हें देश के रक्षा मंत्री पर भरोसा नहीं है, सरकार पर यकीन नहीं है, और तो और देश की न्याय व्यवस्था, माननीय सुप्रीम कोर्ट पर

भी नहीं! वो कई बार रॉफेल के मुद्दे पर जेपीसी की भी मांग कर चुके हैं जो सर्वथा निरर्थक है। क्योंकि इससे पहले जब कैग की रिपोर्ट के आधार पर 2 जी घोटाला प्रकाश में आया था, तब जेपीसी का गठन किया गया था जिसमें सरकार को क्लीन चिट दे दी गई थी लेकिन अदालत ने आरोपियों को जेल भेज दिया था। इसके बावजूद अगर वो जेपीसी की मांग करते हैं तो इसे क्या समझा जाए?

देश जानना चाहता है कि कहीं बोफोर्स की ही तरह रॉफेल भी कांग्रेस का ही षडयंत्र तो नहीं है?

क्योंकि रॉफेल डील 2012 के कांग्रेस के समय की वो अधूरी डील है जो उनके कार्यकाल में पूरी नहीं हो पाई थी। 2015 में मोदी सरकार ने इस डील को आगे बढ़ाया और अब यह डील भारत सरकार और फ्रांस सरकार के बीच है। एयर चीफ मार्शल बीरेंद्र सिंह धनोआ रॉफेल डील को लेकर लगाए गए सभी आरोपों को यह कहकर खारिज कर चुके हैं कि वर्तमान डील पहले से बेहतर शर्तो पर हुई है।

पूर्व एयर चीफ अरूप राहा कह चुके हैं कि जो 36 रॉफेल विमानों का सौदा हुआ है वो पुराने प्रपोजल से बेहतर है क्योंकि ये बेहतर टेक्नोलॉजी और हथियारों से लैस हैं।

अब इसे क्या कहा जाए कि एक तरफ राहुल गांधी हमारे सैनिकों से कहते हैं कि आप हमारे गर्व हो और दूसरी तरफ वो हमारे सेनाध्यक्षों पर भी यकीन नहीं कर रहे?

अभी हाल ही में जिस अधूरी चिट्ठी को दिखाकर वो प्रधानमंत्री को घेरने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं उसमें वो भले ही राजनीति के चलते रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण के ब्यान पर भरोसा नहीं कर रहे ठीक है, लेकिन कम से कम देश की सेना पर तो यकीन करें जिस पर वो अपने ही कहे अनुसार गर्व करते हैं। क्योंकि खुद रॉफेल सौदे के वार्ताकार एयर मार्शल एसबीपी सिन्हा ने ही राहुल के आरोप को यह कह कर खारिज कर दिया कि पीएमओ ने कभी भी रॉफेल सौदे में दखलंदाजी नहीं की। इसके अलावा जिन तत्कालीन रक्षा सचिव जी मोहन कुमार के नोट को राहुल मुद्दा बना रहे हैं वो ही यह कह रहे हैं कि मेरी टिप्पणी का रॉफेल जेट की कीमतों से कोई लेना देना नहीं था, मैंने सिर्फ सामान्य शर्तो की बात की थी।

यह हैरत की बात है कि राहुल पूरी चिट्ठी से संतुष्ट नहीं होते, सेनाध्यक्षों के बयान से संतुष्ट नहीं होते, फ्रांस के राष्ट्रपति के बयान से संतुष्ट नहीं होते लेकिन एक अंग्रेजी अखबार में प्रकाशित अधूरी खबर से इतने संतुष्ट हो जाते हैं कि प्रेस कांफ्रेंस ही बुला लेते हैं। तो आइए अब उस अखबार के एडिटर के बारे में भी कुछ रोचक तथ्य जान लें जिनकी रिपोर्ट पर ताजा विवाद हुआ। इसके लिए हमें इतिहास में थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। ये समय था 1986 का जब स्वीडन के रेडियो पर बोफोर्स सौदे में दलाली की खबर पहली बार सामने आई। तब भारत में लोग इस बात से अनजान थे। उस समय इसी अंग्रेजी अखबार की एक महिला रिपोर्टर किसी अन्य स्टोरी के सिलसिले में स्वीडन में थी। इस रिपोर्टर ने बोफोर्स घोटाले के सुबूतों के तौर पर लगभग 350 से अधिक दस्तावेज हासिल किए।

तब बोफोर्स में दलाली की खबर छापने वाले यही एडिटर थे। लेकिन इस मामले में यह खबर इन एडीटर की आखरी खबर भी सिद्ध हुई। उसके बाद से बोफोर्स मुद्दा इन एडिटर की कवरेज से गायब हो गया। और आज वो ही एडीटर रक्षा मंत्रालय के एक नोट का अधूरा अंश छाप कर क्या सिद्ध करना चाहते है? ऐसे संवेदनशील विषय पर क्या उन्हें रक्षा मंत्रालय का पक्ष भी रखकर देश के एक जिम्मेदार नागरिक होने का कर्तव्य नहीं निभाना चाहिए था? क्योंकि बात केवल इतनी ही नहीं है कि एक प्रतिष्ठित अंग्रेजी अखबार का एडीटर अधूरे तथ्यों से आधा सच सामने रखता है जिसका सहारा लेकर राहुल देश को गुमराह करके राजनैतिक लाभ लेने की कोशिश करते हैं। बात यह है कि मुख्यधारा का मीडिया अपनी विश्वसनीयता खोता जा रहा है। इसलिए अगर राहुल चाहते हैं कि देश उन्हें सीरियसली ले तो वो भ्रष्टाचार के हर मुद्दे पर अपनी चिंता व्यक्त करें, भ्रष्टाचार के हर मामले के खिलाफ खड़े हों केवल मोदी के खिलाफ नहीं।

कर्ज में डूबे प्रदेश के बजट में सौगातों की बौछार

शिमला/शैल। मुख्यमन्त्री जयराम ठाकुर ने विधान सभा में 44,387.73 करोड़ रुपए का बजट, वर्ष 2019-20 के लिए पेश किया । बजट में सौगातों की बरसात कर दी गई हैं। 2019-20 में राजस्व प्राप्ति 33,747 करोड़ रुपये संभावित है और राजस्व व्यय 36,089 करोड़ रुपये सम्भावित है। इस तरह से राजस्व घाटा 2,342 करोड़ रुपये और वित्तीय घाटा 7,352 करोड़ रुपये होने की संभावना है। वित्तीय घाटा जीडीपी का 4.3 प्रतिशत होने का अनुमान है। 2019-20 में 5069 करोड़ रुपये कर्ज लेने का अनुमान है जो एफआरबीएम एक्ट के अनुसार तय सीमा के अनुरूप होगा। बजट में कुछ प्रमुख बिन्दुओं पर विशेष ध्यान दिया गया है जो इस प्रकार से है।

➪ आर्थिक रूप से पिछड़े सामान्य वर्ग के परिवारों को, नौकरी व शैक्षणिक संस्थानों में 10 प्रतिशत दिया जाएगा।

➪ सामाजिक सुरक्षा पैंशन को 750 रुपये से बढ़ाकर 850 रुपये प्रतिमाह और 1,300 रुपये प्रतिमाह पैंशन राशि को बढ़ाकर 1,500 रुपये प्रतिमाह किया गया। 5 लाख से अधिक परिवारों को सीधा लाभ।

➪ हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना और केन्द्रीय उज्जवला योजना के लाभार्थियों को एक अतिरिक्त गैस रिफिल मुफ्त दिया जाएगा। 2 लाख महिलाओं को फायदा। केन्द्र की उज्जवला योजना के नए लाभार्थियों को प्रदेश सरकार अपने संसाधनों से गैस, चूल्हा और पाईप देगी।

➪ दिहाड़ीदारों की दिहाड़ी 750 रुपये प्रति माह बढ़ाई गई। अंशकालिक कर्मियों की दिहाड़ी में बढ़ौतरी भी की जाएगी। आँगनबाड़ी कार्यकताओं, आँगनबाड़ी सहायकों, मिनी आँगनबाड़ी कार्यकताओं, आशा कार्यकताओं, वाटर गार्ड, स्कूलों के वाटर कैरियर्ज, मिड डे मील्ज कार्यकताओं एवं सहायकों, पम्प ऑपरेटर्ज, पैरा फिटर्ज, पंचायत चौकिदारों, राजस्व चौकीदारों और का मानदेय बढ़ाया गया।

➪ 1 जुलाई, 2018 से प्रदेश के कर्मचारियों को 4 प्रतिशत की दर से मंहगाई भत्ता तथा पेंशनधारकों को मंहगाई राहत दी जाएगी।

➪ अनुबन्ध कर्मचारियों के वेतन में बढ़ौतरी। उनके वेतन और ग्रेड पे में 125 प्रतिशत की दर से राशि जोड़ी जाएगी जो कि पहले 100 प्रतिशत होती थी। पीएटी पैरा शिक्षकों के वेतन में बढ़ौतरी ।

➪ आपातकाल के दौरान मिसा कानून के तहत हुई गिरफ्तारियों से प्रताड़ित व्यक्तियों को 11,000 रुपये सालाना लोक तंत्र प्रहरी सम्मान राशि प्रदान की जाएगी।

➪ बिजली पर सब्सिडी के लिये 475 करोड़ रुपए का प्रावधान।

➪ पंचायत बीडीसी व जिला परिषद सदस्यों के मानदेय को बढ़ा दिया गया हैं।

➪ विभिन्न ग्रामीण आवासीय योजनाओं के अन्तर्गत जहां अभी घर बनाने के लिये 1,30,000 रुपये दिये जाते हैं, वहां 20,000 रुपये अतिरिक्त उपदान राशि प्रति लाभार्थी राज्य सरकार अपने संसाधनों से देगी।

➪ मुख्यमन्त्री आवास योजना के तहत मुरम्मत हेतु सहायता राशि बढ़ाकर 35,000 रू0 की गई । मादक पदार्थों की तस्करी तथा प्रयोग को रोकने के लिए मुख्यमन्त्री की अध्यक्षता में युवा नव जीवन बोर्ड की स्थापना की जाएगी व 5 नशा निवारण एवं पुनर्वास केन्द्रों की स्थापना की जाएगी।

➪ बीमारियों से ग्रस्त गरीब मरीजों को आर्थिक सहायता देने के उद्देश्य से एक नई योजना सहारा का आरम्भ किया जाएगा। Parkinson"s, Cancer, Paralysis, Muscular Dystrophy, Haemophilia, Thalsaemia, Renalf ailure वाले मरीजों को 2000 रुपये प्रतिमाह की सहायता दी जाएगी।

➪ एच.आई.वी. एड्स से संक्रमित व्यक्तियों के भत्ते को बढ़ाकर 1,500 रुपये प्रति माह किया जाएगा।

➪ जननी सुरक्षा योजना के अन्तर्गत प्रसूताओं की प्रोत्साहन राशि को बढ़ाकर 1,100 रुपये किया जाएगा।

➪ ब्रेस्ट तथा सरवाईकल कैंसर की रोकथाम के लिये मोबाइल डॉयगनोस्टिक वैन तैनात किये जाएंगे।

➪ 45 वर्ष से कम आयु की विधवाओं के लिए नर्सिंग शिक्षण संस्थानों व आइटीआई में दाखिले के लिए आरक्षण तथा कौशल प्रशिक्षण एवं रोजगार हेतु आवश्यक सहायता का प्रावधान किया गया है। परित्यक्ता महिलाओं को बच्चों की देखभाल के लिए वित्तीय सहायता 6,000रू. तक प्रति बच्चा बढ़ाई गई।

➪ 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर बाल आश्रम में रह रहे बच्चों के लिये आफ्टर केयर होम स्थापित किए जाएंगे तथा ऐसे बच्चों को फलेक्सी आइटीआई के अन्तर्गत कौशल प्रशिक्षण भी दिया जाएगा।

➪ 50 दिनों से ज्यादा काम करने वाले मनरेगा लाभार्थी और सामाजिक सुरक्षा पाने वाली विधवाओं को पैंशन योजना के लाभ बिना किसी प्रीमियम के दिए जाएंगे।

➪ केन्द्रीय सरकार द्वारा घोषित प्रधानमन्त्री किसान योजना को प्रदेश में अतिशीघ्र लागू करने हेतु आवश्यक कदम उठाए जाएंगे । इस योजना से प्रदेश के 8.50 लाख से अधिक किसान लाभान्वित होंगे।

➪ प्रदेश सरकार ने किसानों लिए कई नई योजनाएं व कार्यक्रम आरम्भ किए हैं। 150 करोड़ रुपये की मुख्यमन्त्री नूतन पॉली हाऊस योजना, एंटी हेलनेट के लिये दोगुना बजट, कई सिंचाई एवं बाढ़ प्रबन्धन योजनाएं, मुख्यमंत्री खुंब विकास योजना, स्वदेशी नस्ल की गायों के लिये 5,000 रू. तक का उपदान, दूध खरीद पर 2 रुपये प्रति लीटर की वृद्धि, ऐसे प्रस्ताव हैं जिनसे ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार और आय के अवसर बढ़ेंगे। पिछले बजट में घोषित योजनाओं को भी प्रभावी ढंग से लागू किया जाएगा।

➪ मुख्यमन्त्री स्वजल योजना के तहत गरीब परिवारों को घरों में नलका लगाने के लिये 50 मीटर तक पाईप के लिए 50 प्रतिशत उपदान दिया जाएगा।

➪ मुख्यमन्त्री रोशनी योजना आरम्भ की जाएगी जिसके तहत गरीब परिवारों को नए विद्युत कनेक्शन हेतु कोई सर्विस कनेक्शन चार्जिज नहीं देने पड़ेंगे। इन चार्जिज को प्रदेश सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।

➪ प्रदेश की 500 बस्तियों को स्वच्छ पेयजल सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी।

➪ हिमाचल प्रदेश बाढ़ एवं नदी प्रबन्धन परियोजना के पहले चरण में 1,235 करोड़ रुपये तथा दूसरे चरण में 1,850 करोड़ रुपये की बाह्य सहायता एजेंसी के वित्तपोषण हेतु संस्तुति की गई है। 11.21 करोड़ रुपये की लागत से साहीवाल व रेडसिंधी पशुधन प्रजनन फार्म स्थापित किया जाएगा

➪ गरीबी रेखा से नीचे रह रहे किसानों की आय को बढ़ाने के लिये 85 प्रतिशत उपदान पर बकरियां उपलब्ध करवाई जाएंगी।

➪ उन्नत नस्ल की भेड़ों का आयात किया जाएगा। 11 करोड़ रुपये की लागत से मुर्रा नस्ल की भैंसों का फार्म स्थापित किया जाएगा। प्रदेश में एक गोकुल ग्राम भी स्थापित किया जाएगा ।

➪ दतनगर जिला शिमला एवं चक्कर जिला मण्डी में 50,000 लीटर प्रतिदिन क्षमता के दूध प्रसंस्करण संयंत्र स्थापित किये जाएंगे।

➪ परम्परागत कौशल और शिल्प ग्राम कारीगर, शिल्पी एवं अन्य कुशल कामगारों के लिये मुख्यमन्त्री ग्राम कौशल योजना प्रारम्भ होगी।

➪ ग्रामीण क्षेत्रों में 26,000 लकड़ी के खम्बे लोहे के खम्बों से बदले जाएंगे ताकि नियमित बिजली मिले।

➪ किसानों के लिए सिंचाई के लिए बिजली की दरें कम करके 50 पैसे प्रति युनिट की गई ।

➪ धार्मिक पर्यटन को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से मण्डी जिले में शिव धाम स्थापित किया जाएगा।

➪ मुख्यमन्त्री स्वावलम्बन योजना के तहत अधिकतम आयु सीमा तथा अधिकतम निवेश सीमा बढ़ाई जा रही है।

➪ कौशल विकास भत्ता योजना के तहत लगभग 1 लाख युवाओं को कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा।

➪ कौशल विकास निगम द्वारा 40,000 युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा।

➪ ग्रामीण दस्तकारों का कौशल बढ़ाने हेतु मुख्यमन्त्री ग्राम कौशल योजना आरम्भ की जाएगी।

➪ नई योजना नवधारणा के तहत दिव्यांगजनों के लिये कौशल विकास कार्यक्रम आरम्भ किया जाएगा।

➪ विधायक क्षेत्र विकास निधि से विधायक पंजीकृत युवक मण्डलों को 25,000 रुपये तक की खेल सामग्री व खेल उपकरण प्रति युवक मण्डल प्रदान कर पाएंगे। प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में मुख्य मन्त्री युवा निर्माण योजना के तहत दो नए खेल के मैदान बनाये जायेंगे।

➪ एसएस. बी. कोचिंग हेतु प्रोत्साहन राशि 6,000 रुपये से बढ़ाकर 12,000 की जाएगी।

➪ सरकार 2019-20 में लगभग 20,000 पद भरेगी।

➪ 15 नये अटल आदर्श विद्या केन्द्र प्रदेश के विभिन्न विधान सभा क्षेत्रों में स्थापित किये जाएंगे।

➪ खेल से स्वास्थ्य योजना आरम्भ की जाएगी।

➪ नई योजना एक बूटा, बेटी के नाम लागू की जाएगी।

➪ परफार्मिंग आर्टस में प्रोत्साहन हेतु कलाकार प्रोत्साहन योजना शुरु की जाएगी ताकि हिमाचल के होनहार बच्चे प्रमुख राष्ट्रीय संस्थानों में दाखिला ले सकें।

➪ संस्कृत को दूसरी राजकीय भाषा का दर्जा ।

➪ प्रदेश भर की 100 पुलिस चौकियों को रिपोर्टिंग पुलिस चौकियों के तौर पर नामित किया जाएगा। मुख्य आरक्षियों को भी आबकारी मामलों की जाँच के लिये अधिकृत किए जाने का प्रस्ताव है।

➪ GST में पंजीकरण हेतु वार्षिक टर्नओवर सीमा को 40 लाख रुपये तक बढ़ाया जाएगा। टर्नओवर की कम्पोजिशन लिमिट को बढ़ाकर 1.50 करोड़ रुपये किया जाएगा।

➪ एन.पी.एस. के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा दिए जाने वाले 10 प्रतिशत अँशदान को 14 प्रतिशत किया जाएगा। इससे 80,000 कर्मचारियों को लाभ मिलेगा।

➪ सरकार एक नई सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग नीति लेकर आएगी।

➪ 2019 में धर्मशाला में एक 'Global Investors Summit' का आयोजन किया जाएगा।

➪ ''पौंग क्षेत्र विकास बोर्ड'' का गठन किया जाएगा। यह बोर्ड पौंग क्षेत्र के समुचित एवं सुनियोजित विकास बारे नीति एवं कार्यक्रम निर्धारित करेगा।

➪ पर्यटन विकास और प्रोत्साहन क्षेत्र के लिये नई पर्यटन नीति तैयार की जाएगी। राज्य सरकार ईको-टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिये मास्टर प्लान तैयार करेगी। होम स्टे स्कीम को बढ़ावा देने के लिए कमरों की संख्या बढ़ाकर 4 की जाएगी।

➪ बाह्य सहायता से 1,892 करोड़ रुपये की पर्यटन आधारभूत संरचना परियोजना आरम्भ की जा रही है।

➪ प्रदेश के प्रमुख शहरों के लिये हैली टैक्सी सेवाएं शुरु की जाएंगी।

➪ परिवहन निगम में Integrated Public Transport Management System IPTMS) प्रणाली की स्थापना की जाएगी।

➪ प्रदेश का नया रोपवे उपक्रम यानि ÙTDC, शिमला और मनाली में ओवरहैड मास रैपिड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम स्थापित करने के लिये Pre-feaibility study कराएगा।

➪ नई इलैक्ट्रिकल व्हीकल पॉलिसी बनाई जाएगी।

➪ 750 किलोमीटर नई सड़कों का निर्माण, 850 किलोमीटर लम्बाई की सड़कों पर पुलियों का निर्माण, 1,500 किलोमीटर पक्की सड़कों का निर्माण, 50 पुलों का निर्माण किया जाएगा तथा 50 नए गाँवों को सड़क सुविधा से जोड़ा जाएगा।

➪ सड़कों के निर्माण तथा रख-रखाव के लिये Indian Road Congres:IRC) मान्यता प्राप्त गैर-पारंपरिक सामग्री और नई तकनीक का उपयोग पॉयलट आधार पर किया जाएगा।

➪ 500 मैगावाट क्षमता की बिजली परियोजनाएं चालू होने की सम्भावना है। इसमें राज्य विद्युत बोर्ड की 100 मैगावाट क्षमता वाली ऊहल-तृतीय चरण तथा हि. प्र. पावर कॉरपोरेशन की 111 मैगावाट क्षमता वाली सावड़ा कुद्दू परियोजनाएं शामिल हैं। चांजू-3 और दियोथल चांजू बिजली परियोजनाओं का कार्य शुरू किया जाएगा।

➪ मुख्यमन्त्री स्वावलम्बन योजना के तहत अधिकतम आयु सीमा तथा अधिकतम निवेश सीमा बढ़ाई जा रही है।

➪ 50 ITIs को अपग्रेड कर आधुनिक बनाया जाएगा । इससे 5,500 अतिरिक्त विद्यार्थी ITIs में दाखिला ले सकेंगे। भंजराडू, तीसा, अम्बोया, सतौन और लडभड़ोल में 5 नई ITIs खोली जाएंगी । करसोग और दलाश में नए पौलीटैक्निक खोले जाएंगे ।

➪ खेल-कूद प्रतिभा खोज कार्यक्रम शुरु किया जाएगा ।

➪ 500 स्वास्थ्य उप-केन्द्रों तथा 125 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को स्वास्थ्य एवं वेलनैस केन्द्रों में परिवर्तित किया जाएगा।

➪ सम्पूर्ण स्वास्थ्य योजना के तहत 12 स्वास्थ्य संस्थानों को स्तरोन्नत किया जाएगा।

66. लाल बहादुर शास्त्री आयुर्विज्ञान महाविद्यालय मण्डी एवं डॉ. वाई. एस. परमार राजकीय आयुर्विज्ञान महाविद्यालय, नाहन में हृदय एवं सम्बन्धित रोगों के उपचार के लिये Cath Labs की स्थापना की जाएगी।

➪ इन्दिरा गान्धी मेडिकल कॉलेज शिमला में Digital Subtraction Angiography Machine स्थापित की जाएगी।

➪ चम्बा जिला अस्पताल में 100 बिस्तरों वाला एक मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य विंग स्थापित किया जाएगा।

➪ ब्रेस्ट तथा सरवाईकल कैंसर की रोकथाम के लिये Mobile Diagnostic Vans तैनात की जाएंगी। यह मोबाईल वैन प्रदेश के कैंसर अस्पतालों के साथ मिलकर इन बिमारियों को रोकने के लिये कार्य करेंगी।

ठोस कचरा निपटान में सभी का सहयोग जरूरी:सरवीण चौधरी

शिमला/शैल। शहरी विकास, नगर नियोजन एवं आवास मंत्री सरवीण चौधरी ने कहा कि स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत प्रदेश के सभी 54 शहरी स्थानीय निकायों के सभी आवसों में शौचालय सुविधा प्रदान करने के लिए लाभार्थियों की पहचान की गई है।

सरवीण चौधरी सोलन जिला के नालागढ़ उपमण्डल में घरेलू परिसंकटमय अपशिष्ट संग्रहण एवं जागरूकता क्योस्क का शुभारंभ करने के उपरांत उपस्थित जनसमूह को संबोधित कर रही थी।

उन्होंने इस अवसर पर 3.50 लाख रुपये की लागत से निर्मित किए गए ठोस कचरा प्रबंधन संग्रहण केन्द्र का लोकार्पण भी किया।

सरवीण चौधरी ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण एवं नागरिकों के स्वास्थ्य के दृष्टिगत शहरी ठोस कूड़े का समुचित प्रबंधन करना नितांत आवश्यक है। इसके सुचारू संचालन के लिए वर्तमान सरकार योजनाबद्ध कार्य कर रही है। उन्होंने शहरी ठोस कूड़े के उचित प्रबंधन के लिए नागरिकों, उद्योगों व गैर सरकारी संगठनों को नगर पालिकाओं को सहयोग करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि प्लास्टिक, कांच व कागज जैसे पुन: उपयोग में लाए जाने वाले अकार्बनिक पदार्थों को कूड़े से छंटनी करने के लिए आम जन को समय-समय पर प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

उन्होंने कहा कि कूड़ा-कचरा से कई प्रकार की बीमारी फैलती है जो सभी के लिए हानिकारक है। उन्होंने नगर परिषद के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे सब्जी मण्डी से कूड़ा कचरा एकत्रित कर इसका प्रयोग खाद बनाने के लिए करें। उन्होंने लोगों से आह्वान किया कि कचरे को बारिश के पानी व नालियों में न फेंके। उन्होंने कहा कि इंजेक्शन, पुरानी दवाएं, पेपर में लपेटा सेनेटरी नैपकीन व डायपर्स, उपयोग किया बैंडेज, रूई, पेप रोल को अलग डस्टबिन में रखें।

शहरी विकास मंत्री ने कहा कि नालागढ़ में 60 लाख रुपये की लागत से पार्क का निर्माण किया जाएगा। इस पार्क के निर्मित होने से जहां पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा वहीं स्थानीय लोगों को टहलने के लिए स्थान उपलब्ध होगा।

स्वयं सहायता समूहों से आत्मनिर्भर बन रही महिलाए

शिमला/शैल। कांगड़ा जिला में महिलाओं को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित करने एवं आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य के साथ स्वयं सहायता समूहों के गठन पर बल दिया जा रहा है। इस काम में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन बहुत सहयोगी सिद्ध हो रहा है। मिशन के तहत महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों को

डिस्पोजल कप, प्लेट, सिलाई कढ़ाई, स्वैटर बुनाई, पापड़-बड़ियां, आचार-चटनी बनाने जैसे कार्यो का प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिससे वे आत्मनिर्भर बन रही हैं।

नूरपुर विकास खण्ड की मिल्ख पंचायत के गांव क्योड़ धारियां की दस महिलाओं ने भी राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का लाभ उठा कर अपनी सफलता की नई कहानी गढ़ी है। इन महिलाओं ने साथ मिलकर वर्ष 2011 में कृषक महिला स्वयं सहायता समूह का गठन किया था। साल 2014 में इन्होंने केंद्र सरकार की राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत लाभ लिया। समूह की सदस्यों ने खंड विकास अधिकारी कार्यालय नूरपुर के सौजन्य से डिस्पोजल सिलाई कढ़ाई, कप, प्लेट, बनाने का 15 दिन का प्रशिक्षण लेकर अपना काम शुरू किया। कार्यक्रम के तहत् समूह को डीआरडीए की ओर आरंभ में 15 हजार रूपये सहायता राशि उपलब्ध करवाई गई। महिलाओं ने इस कार्य में बहुत रूचि के साथ काम किया और प्रशिक्षण के बाद इनका डिस्पोजल कप, प्लेट, आचार, चटनी, सेमियां, बड़िया, स्वेटर बनाने का काम चल निकला और देखते ही देखते उनके दिन बदलने लगे।

कृषक महिला स्वयं सहायता समूह की प्रधान रीतू बताती हैं कि स्वयं सहायता समूह में जुड़ने से पहले सभी महिलाएं घरेलू स्तर पर आर्थिक समस्याओं से जूझ रहीं थी, लेकिन समूह से जुड़ने के बाद इन सभी महिलाओं की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है। डिस्पोजल कप, प्लेटों तथा सिलाई कढ़ाई, आचार, चटनी, सेमियां, बड़ियों के उत्पादों की गांवों में खूब मांग रहती है और यह सब सामान उपलब्ध करवा कर वे सभी अच्छी खासी आमदनी प्राप्त कर रही हैं।

रीतू आगे बताती हैं कि इस काम को और बढ़ाने के लिए सभी ने मिलकर एक लघु उद्योग स्थापित करने की सोची। इसके लिए समूह को एक बड़ी राशि की जरूरत थी। उन्होंने बैंक से ऋण लेने के बारे में सोच विचार किया। खंड विकास कार्यालय की सहायता से बैंक से आसानी से 3 लाख रुपए का लोन मिल गया। जिससे उन्होंने डिस्पोजल कप, प्लेट बनाने की एक मशीन खरीदी और कार्य आरम्भ कर दिया। शुरू-शरू में उन्हें कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ा लेकिन वे हिम्मत के साथ कार्य करती रहीं। अब समूह की सदस्यों ने अपनी कमाई से अब तक 2 लाख 30 हजार रुपये का लोन भी वापिस कर दिया है।

स्वयं सहायता समूह की आयोजक सदस्य नीतू बताती हैं कि अब काम अच्छा चल निकला है, शादी-ब्याह, या त्यौहारों के सीजन में उनके उत्पादों की खूब मांग रहती है। इससे समूह से जुड़ी हर सदस्य को महीने के लगभग 5 हजार रुपये कि कमाई हो रही है।

समूह की अन्य सदस्यों ने एक स्वर में कहा कि समूह में जुड़ने से सभी को आपसी सहयोग, मिलजुल कर रहना, ईमानदारी से कार्य करना, मुसीबत में एक दूसरे की सहायता करने की प्रेरणा मिलती है। उनका कहना है कि स्वयं सहायता समूह का गठन उनके लिए वरदान साबित हुआ है। चहुंओर से मिल रहे प्रोत्साहन से हौंसला बढ़ा है ओर अब वे सभी मिलकर अपने काम को और बढ़ाने का सोच रही हैं।

डीआरडीए कांगड़ा के परियोजना अधिकारी मुनीष शर्मा बताते हैं कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित एक गरीबी उन्मूलन परियोजना है। यह योजना ग्रामीण गरीबों के स्वरोजगार और संगठन को बढ़ावा देने पर केन्द्रित है। इस कार्यक्रम के पीछे मूल विचार गरीबों को स्वयं सहायता समूहों में संगठित करना और अच्छे स्वरोजगार के लिए सक्षम बनाना है।

जिलाधीश कांगड़ा संदीप कुमार का कहना है कि जिले में महिला कल्याण गतिविधियों को बढ़ावा देने पर बल दिया गया है तथा महिलाओं को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित करने के लिए अनेक कदम उठाये गये है। महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों से जोड़कर आर्थिक सुदृढ़ीकरण के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। जिला प्रशासन की ओर से महिलाओं सहित सभी लोगों को स्वरोजगार से आत्मनिर्भर बनाने के लिए हर संभव सहायता उपलब्ध करवाने पर विशेष बल दिया जा रहा है।

उनका कहना है कि इस कार्य में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन बड़ा सहायक सिद्ध हो रहा है। इसके तहत स्वयं सहायता समूहों को 25-25 हजार रिवॉलविंग फंड दिया जाता है, साथ ही बैंकों से सस्ती दरों पर लोन की व्यवस्था की जाती है। जिससे उन्हें अपना काम शुरू करने में सहुलियत रहती है।

मनरेगा कार्यकर्ताओं को कामगार कल्याण बोर्ड के तहत पंजीकृत करवाएं:संदीप कुमार

शिमला/शैल। उपायुक्त संदीप कुमार ने धर्मशाला में कांगड़ा जिला के विकास खंडों में कार्यान्वित की जा रही विभिन्न सरकारी योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए खण्ड विकास अधिकारियों को अपने क्षेत्रों में सभी पात्र मनरेगा कार्यकर्ताओं का कामगार कल्याण बोर्ड में पंजीकरण करवाना तय बनाने को कहा। उन्होंने कहा कि मनरेगा के तहत काम करने से होने वाले लाभों के बारे में लोगों को जागरुक किया जाए । 90 दिनों तक मनरेगा में काम करने पर लोग कामगार कल्याण बोर्ड में पंजीकरण के लिए पात्र हैं और वे बोर्ड की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ ले सकते हैं। उपायुक्त ने कहा कि इस कार्य में खण्ड विकास अधिकारियों की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। वे तय करें कि पात्र मनरेगा कार्यकर्ता लाभ से वंचित न रहें, इसके लिये रणनीति बना कर काम करें।

गौरतलब है कि हिमाचल भवन एवं अन्य निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड पंजीकृत श्रमिकों के लिए निशुल्क सोलर कुकर, इंडक्शन हीटर बर्तन सहित, वाशिंग मशीन देने के अलावा शादी, पढ़ाई-लिखाई, चिकित्सा और अन्य कार्यो में सहायता के लिए धन राशि उपलब्ध करवाने की अनेक योजनाओं कार्यान्वित करता है।

उन्होंने कहा कि मनरेगा में जो पंचायतें अच्छा काम कर रही हैं, अन्य पंचायतों के जन प्रतिनिधियों को वहां का दौरा करवाएं, ताकि वे प्रेरणा लेकर अपने क्षेत्रों में मनरेगा कामों को गति दे सकें। उन्होंने खंड विकास अधिकारियों को उनके कार्यालय से जुड़े जनमंच के मामलों का अविलंब निपटारा सुनिश्चित बनाने के निर्देश दिए।

इस मौके उपायुक्त ने मनरेगा के साथ साथ प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना, राष्ट्रीय आजीविका मिशन, स्वच्छ भारत मिशन, मुख्यमंत्री लोक भवन योजना, आंगनबाड़ी भवन निर्माण, पंचायती राज विभाग, राजस्व एवं योजना विभाग से जुड़े विकास कार्यो की प्रगति का जायजा लिया।

संदीप कुमार ने कहा कि मनरेगा कार्यकर्ताओं को प्रदेश सरकार की हिम केयर योजना के बारे में जागरूक करें और इससे जोड़ें। हिम केयर योजना में आयुष्मान भारत योजना से छूटे परिवारों के लिए भी प्रति परिवार 5 लाख रुपये तक नि:शुल्क ईलाज का प्रावधान है। उन्होंने कहा कि लोकमित्र केंद्र में यह कार्ड बन रहे हैं।

उपायुक्त ने अधिकारियों से संबंधित क्षेत्रों में आंगनबाड़ी भवनों के निर्माण कार्य में तेजी लाने के लिये अतिरिक्त प्रयास करने को कहा। उन्होंने कहा कि आंगनबाड़ी भवनों के निर्माण के लिये जहां भूमि उपलब्ध नहीं है, वहां भूमि दान करने के लिए दानी लोगों को प्रोत्साहित करें एवं भूमि दान देने वाले लोगों को प्रशासन की ओर से सम्मानित किया जाए।

इसके अलावा जहां भूमि दान के मामले नहीं हैं वहां आंगनबाड़ी के लिए स्थानीय लोगों का सहयोग लेकर जमीन हस्तांतरण के मामले बनाएं। लोगों को बतायें कि आंगनबाड़ी भवन के लिए उपयुक्त जमीन देने पर जिला प्रशासन उन्हें नजदीक में दुगनी सरकारी जमीन उपलब्ध करवाएगा।

उन्होंने कहा कि आंगनबाड़ी और पंचायत भवनों के निर्माण के लिये धन की कोई कामी नहीं है। उपायुक्त कार्यालय को इनसे जुड़े मामले भेजने पर अविलंब धन राशि उपलब्ध कारवाई जाएगी। उन्होंने खंड विकास अधिकारियों से आँगनबाड़ी भवनों के लिये विशेष आकर्षक कलर स्कीम लागू करने का प्रयास करने को कहा।

उपायुक्त ने कहा कि जिला में मिड डे मील योजना को कॉरपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी (सीएसआर) से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। स्कूलों में बच्चों को दिए जाने वाले भोजन में हर सप्ताह एक-एक दिन मशरूम और डेयरी उत्पाद भी दिए जाएंगे। ये उत्पाद जिला में काम कर रहे विभिन्न स्वयं सहायता समूहों से खरीदे जाएंगे। इससे समूहों की आमदनी में भी बढ़ोतरी होगी। यह खर्चा विभिन्न सार्वजनिक और निजी उद्यमों का सहयोग लेकर वहन किया जाएगा।

संदीप कुमार ने कहा कि जिला में 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' अभियान बेहद सफल रहा है। कांगड़ा जिला प्रशासन ने इसमें अब एक नया आयाम जोड़ा है- 'बेटी सक्षम बनाओ'।

उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन ऐसी हर बच्ची की मदद करने के लिए तत्पर है जो किन्ही कारणों से दयनीय स्थिति में जीवन यापन को मजबूर है। ऐसी बच्चियों को पढ़ाने के अलावा उन्हें व्यवसायिक कोर्स करवाने के लिए भी जिला प्रशासन मदद कर रहा है। उन्होंने बताया कि ज्वाली में जनमंच के दौरान ऐसा एक मामला उनके समक्ष आया था जिसमें 17 और 19 साल की दो बहनों के मात-पिता का देहांत हो गया था और बच्चियों को गुजर-बसर के लिए संर्घष करना पड़ रहा था। इस मामले में उन्होंने बड़ी बहन का बीएससी नर्सिंग में दाखिला करवा दिया है और छोटी बहन को बाल संरक्षण कार्यालय की ओर से 25 हजार रुपए की सहायता राशि उपलब्ध करवाई है।

उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन विभिन्न सामाजिक संस्थाओं और शिक्षण संस्थानों के सहयोग से ऐसी जरूरतमंद बच्चियों को व्यवसायिक कोर्स करवाएगा, ताकि वे सक्षम व आत्मनिर्भर बन सकें। उन्हें नर्सिंग, पर्यटन एवं हॉस्पिटैलिटी से जुड़े रोजगारोन्मुखी व्यवसायिक कोर्स करवाने पर बल दिया जाएगा।

उन्होंने कहा कि जरूरत बालकों की भी इस कार्यक्रम के तहत इसी प्रकार मदद की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों से ऐसा कोई भी मामला उनके अथवा संबंधित एसडीएम के ध्यान में लाने का आग्रह किया।

कौशल विकास निगम के एक प्रतिनिधिमंडल की मुख्यमंत्री से भेंट

शिमला/शैल। राज्य सरकार युवाओं के कौशल उन्नयन को सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है ताकि वे नौकरी चाहने वालों के बजाय रोजगार प्रदाता बनें। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने यह बात कौशल विकास निगम के नव नियुक्त राज्य समन्वयक नवीन शर्मा के नेतृत्व में आए एक प्रतिनिधिमंडल को संबोधित करते हुए कही। प्रतिनिधिमण्डल ने मुख्यमंत्री का उन्हें हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम के राज्य समन्वयक नियुक्त करने के लिए धन्यवाद किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार यह भी सुनिश्चित कर रही है कि राज्य के युवाओं को सरकारी के साथ-साथ निजी क्षेत्र में विभिन्न नौकरियों के लिए रोजगार योग्य बनाया जाए। उन्होंने कहा कि कौशल विकास निगम इस दिशा में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है और उद्योगों की मांग के अनुसार युवाओं का कौशल उन्नयन सुनिश्चित कर सकता है। कौशल विकास निगम के राज्य समन्वयक नवीन शर्मा ने मुख्यमंत्री का उनको यह जिम्मेदारी सौंपने के लिए धन्यवाद दिया तथा आश्वासन दिया कि वे मुख्यमंत्री के साथ-साथ राज्य के युवाओं की उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए प्रतिबद्धता और समर्पण के साथ काम करेंगे।

सम्पादक, प्रकाशक एवं मुद्रक श्री बलदेव शर्मा द्वारा ऋचा प्रिंटर्ज एण्ड पब्लिशर्ज़ रिवोली बस अड्डा लक्कड़ बाजार शिमला से प्रकाशित व मुद्रित दूरभाष: 0177-2805015, 94180-15015 फैक्स: 2805015

www.shailsamachar.co.in

सैद्धान्तिक मंजूरी से आगे नही बढ़े प्रदेश को मिले 68 राष्ट्रीय राजमार्ग

शिमला/शैल। प्रदेश को केन्द्र की ओर से 68 राष्ट्रीय राजमार्ग मिले हैं। यह घोषणा विधानसभा चुनावों से बहुत पहले ही कर दी गयी थी। इस घोषणा पर यकीन करने के लिये उस समय केन्द्रिय स्वास्थ्य मन्त्री जगत प्रकाश नड्डा के नाम आया नितिन गडकरी का पत्र भी जारी किया गया था। इस पत्र में यह दावा किया गया था कि इन राजमार्गो को सैद्धान्तिक मंजूरी मिल चुकी है। लेकिन विधानसभा में मुकेश अग्निहोत्री के एक सवाल के जवाब में आयी जानकारी के मुताबिक यह राजमार्ग अभी भी सैद्धान्तिक स्वीकृति से आगे नही बढ़ पाये हैं। इस सदन में कांग्रेस ने वाकआऊट किया और इस पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए आरोप लगाया कि कांग्रेस की सरकार को खनन माफिया चलाता था।

केंद्र सरकार से प्रदेश को 68 सड़कों को बतौर राष्ट्रीय राजमार्गो की सैंद्धातिक मंजूरी मिलने के बाद इनमें से एक को भी असल में मंजूरी न मिलने पर राज्यपाल के अभिभाषण पर हुई चर्चा पर मुख्यमंत्री के जवाब से असंतुष्ट विपक्ष ने सदन से नारेबाजी करते हुए दो बार वाकआउट किया। राज्यपाल के अभिभाषण पर लाए गए धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा में कांग्रेस, माकपा व भाजपा विधायकों की ओर से भाग लेने के बाद चर्चा का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि अभी तो बजट को पास हुए नौ महीने ही हुए हैं। कई घोषणाएं जमीन पर उतर चुकी हैं। बाकियों की औपचारिकताएं पूरी की जा रही हैं।

उन्होंने कहा कि उनकी सरकार का तो अभी एक ही साल पूरा हुआ है। अभी तो चार साल बाकी हैं। हेलीटैक्सी सेवा की शुरूआत कांग्रेस की पूर्व सरकार की 2015 के बजट में की गई घोषणा का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि यह योजना दिसंबर 2018 तक कांग्रेस सरकार शुरू नहीं करा पाई। इससे पहले मुख्यमंत्री ने राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री और बाकी कांग्रेस विधायकों की ओर से यह कहने पर कि एक साल में कुछ भी नहीं हुआ पर आपति जताते हुए कहा कि जमीन पर बहुत कुछ हुआ है व विपक्ष इससे बैचेन हो गया है। राष्ट्रीय राजमार्गो को लेकर मुख्यमंत्री ने इन राजमार्गो को सवा दो साल पहले सैंद्धातिक मंजूरी मिल गई थी। लेकिन इसका भाजपा को राजनीतिक लाभ न मिले इसलिए कांग्रेस की वीरभद्र सिंह सरकार ने इसकी डीपीआर बनाने की प्रक्रिया रोक दी। केवल आठ सड़कों की डीपीआर बनाने का काम आउटसोर्स पर देने की प्रक्रिया शुरू की जबकि केंद्र सरकार ने कहा था कि इन तमाम राजमार्गो पर केंद्र खर्च करेगा। डीपीआर बनाने का खर्च भी केंद्र देगा। लेकिन कुछ नहीं किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने एक साल में 50 सड़कों की डीपीआर बनाने की प्रक्रिया पूरी कर दी है व जल्द ही इनके मंजूर होने पर सभी राष्ट्रीय राजमार्गो को विधिवत तौर पर नंबर भी आवंटित हो जाएंगे। जवाब दे रहे मुख्यमंत्री को टोकते हुए मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि 65 हजार करोड़ में से कितनी रकम मिली। धन्यावाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान विपक्ष के निशाने पर रहे जनमंच कार्यक्रम को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार गांवों में जाकर लोगों की समस्याएं हल करना यह उनकी प्राथमिकता है। अभी 65 हलकों में 106 जनमंच कार्यक्रम हुए हैं और 30 हजार से ज्यादा शिकायतों व मांगपत्रों में से 26हजार 688 को समाधान किया जा चुका है। 277 स्वास्थ्य शिविरों में 45 हजार से ज्यादा लोगो के स्वास्थ्य की जांच की गई। 21 हजार से ज्यादा लाभार्थियों के कागजात बनाए गए। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस कार्यक्रम में कोई किसी से नहीं पूछता कि वह किस पार्टी का है। लोग समस्याएं लेकर आते हैं व उनका समाधान कर दिया जाता है।

हेलीकाप्टर के मसले पर विपक्ष को घेरते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि 2016 में कांग्रेस की सरकार में हेलीकाप्टर पर आठ करोड़ 31 लाख रुपए का खर्च आया। 2017 में आठ करोड़ 78 लाख का खर्च आया लेकिन पिछले एक साल में हेलीकाप्टर पर 7 करोड़ 78 लाख रुपए खर्च आया है। उन्होंने कहा कि उन्होंने सप्ताह में तीन दिन के लिए अपने हेलीकाप्टर को सैलानियों को लाने ले जाने के लिए दे रखा है। लेकिन पिछले साल सितंबर में पहली बार लाहुल स्पिति में भारी बर्फ बारी हुई व उसमें लोग फंस गए। सरकार की प्राथमिकता पर लाहुल स्पिति में फंसे लोग आ गए। बीच में दो महीने यह खराब रहा। तब से लेकर यह वहीं पर लगा हुआ है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने उड़ानों पर उतर पूर्वी राज्यों को उपदान देने की योजना चलाई। कांग्रेस सरकार ने इस योजना का लाभ नहीं उठाया जबकि उनकी सरकार ने इस योजना के तहत केंद्र से सात करोड़ 38 लाख रुपए हासिल कर लिए हैं। यानी जितना खर्च हुआ उतना केंद्र से वसूल लिया।

इस बीच मुकेश ने फिर टोका व कहा कि बजट में जिन योजनाओं की घोषणा की थी उन पर रोशनी डाले। इस बीच दोनों ओर से शोर शराबा हो गया और मुख्यमंत्री बैठ गए। दोनों से शोर – शराबा होता रहा और पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह समेत सभी कांग्रेस विधायकों ने सदन से वाकआउट कर दिया। इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि हर जगह राजनीति करना अच्छी बात नहीं हैं।

कांग्रेस विधायकों की गैरमौजूदगी में मुख्यमंत्री ने कहा कि एक साल में 10 हजार 300 करोड़ की बाहरी वितीय संस्थानों से पोषित योजनाओं को मंजूर कराया गया है। कानून व्यवस्था को लेकर उन्होंने कहा कि पहले अपराध होता था तो अपराधी पकड़े नहीं जाते थे। लेकिन अब यह सुनिश्चित कर दिया गया है कि अपराधियों को सजा मिलेगी ही। उन्होंने कहा कि 2018 में 19594 एफआइआर दर्ज हुई है व इनमें मादक पद्धार्थो से जुड़े मामले में 32 फीसद की बढ़ोतरी हुई है। पिछली सरकार में नशे का कारोबार करने वाले लोग पकड़े ही नहीं जाते थे। किसी को पकड़ लिया गया तो पकड़ने वाले का ही तबादला हो जाता था। लेकिन अब किसी को छोड़ा नहीं जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछली सरकार में खनन माफिया सरकार को चला रहा था। कोई पूछने वाला नहीं था और ऐसे ही माफियाओं ने सरकार को दफन भी कर दिया। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार में 6789 चलान कर तीन करोड़ 33 लाख जुर्माना लगाया गया 36 मामले दर्ज किए गए। उन्होंने कहा कि अपराधी छूटे न सरकार यह सुनिश्चिति कर रही है।

इससे पहले प्रश्नकाल के दौरान राष्टकृीय राजमार्गो के मसले पर मुख्यमंत्री के जवाब से असंतुष्ट होकर कांग्रेस के सभी विधायकों ने नारेबाजी करते हुए सदन से वॉकआउट कर दिया। मुख्यमंत्री ने मुकेश अग्निहोत्री की ओर से पूछे प्रश्न के जवाब में कहा था के प्रदेश सरकार ने केंद्र से सभी राष्ट्रीय राजमार्गो की मंजूर करने का मामला उठाया है। इस पर मुकेश ने कहा कि अभी तक एक भी राजमार्ग मंजूर नहीं हुआ है। ऐसे में प्रदेश सरकार इस मसले पर पिछले एक साल से शोर मचा रही है कि प्रदेश को 70 राजमार्ग मिल गए जबकि जमीनी असलियत कुछ और है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि डीपीआर तैयार कर दी गई है। प्रक्रियाओं को पूरा किया जा रहा है। केंद्र से डीपीआर के लिए 173 करोड़ मिल चुका है।

इससे पहले कि विधानसभा स्पीकर राजीव बिंदल प्रश्नकाल समाप्त करने की घोषणा करते नरेबाजी करते हुए सभी कांगेस विधायकों ने सदन से वाकआउट कर दिया ।

जयराम सरकार के एक साल पूरा होने पर धर्मशाला में आयोजित की गई जन आभार रैली पर सरकारी खजाने से 2 करोड़ 31 लाख 41 हजार 187 रुपए खर्च किए गए है। इस रैली के लिए 44 सरकारी व 63 बसें लगाई गई थी। याद रहे इस रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खासतौर पर शिरकत की थी।

प्रश्नकाल के दौरान कांग्रेस विधायक जगत सिंह नेगी की ओर से पूछे गए प्रश्न के जवाब में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर द्वारा लिखित में यह जानकारी दी गई।

हमीरपुर में फिर बदले भाजपा के समीकरण

शिमला/शैल। हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के भाजपा के प्रवक्ता रहे दीपक शर्मा अब फिर से कांग्रेस में शामिल हो गये हैं। एक समय पूर्व मुख्यमन्त्री प्रेम कुमार धूमल के प्रभाव से ही भाजपा में शामिल हुए थे यह आम चर्चा है। उस समय विनोद ठाकुर भाजपा छोड़ कर कांग्रेस में चले गये थे। अब विनोद ठाकुर फिर से भाजपा में शामिल हो गये हैं। इस बदलाव को आने वाले लोकसभा चुनावों के साथ जो जोड़कर देखा जा रहा है।

पूर्व सीएम धूमल व उनके बेटों की ओर हाशिए से खफा होकर मई 2017 में भाजपा छोड़ कांग्रेस का हाथ थामने वाले आरएसएस नेता विनोद ठाकुर फिर भाजपा में लौट आए हैं। उन्होंने शिमला में फिर से भाजपा ज्वाइन कर ली है। विनोद ठाकुर युवा मोर्चा के तीन बार प्रदेश महामंत्री, युवा मोर्चा राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य, भाजपा के चार साल तक हमीरपुर जिला महामंत्री और दो बार राज्य सचिव के पद पर रहे हैं। माना जा रहा पूर्व सीएम धूमल की हार के बाद भाजपा में हुए धूवीकरण का लाभ विनोद ठाकुर को मिला है। विनोद ठाकुर से पहले धूमल के खास राजेंद्र राणा और उर्मिल ठाकुर भी भाजपा छोड़ कांग्रेस का दामन थाम चुके हैं। खास बात यह है कि ये तीनों ही नेता धूमल के खासमखास रहे हैं।

विनोद ठाकुर मई, 2017 में अपने 33 समर्थकों सहित कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए थे। उस वक्त मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह गांधी चौक पर जनसभा कर रहे थे। विनोद ठाकुर ने कांग्रेस में शामिल होते हुए पूर्व सीएम धूमल पर सीधे हमला करते हुए कहा था कि धूमल परिवार ने हमीरपुर में किसी भी भाजपा नेता को आगे बढ़ने नहीं दिया। उन्होंने धूमल पर हमला करते हुए यहाँ तक कह दिया था कि 1995 में भाजपा से जब जिला परिषद का टिकट मांगा तो नहीं दिया गया। आजाद प्रत्याशी के तौर पर जिला परिषद का चुनाव जीता। भाजपा में 22 वर्ष संगठन का कार्य किया लेकिन जिस तरह से उनका उत्पीड़न धूमल व परिवार ने किया उससे तंग होकर कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए। विनोद ठाकुर ने आरोप लगाया था कि धूमल के हाथ में एक प्राइवेट लिमिटेड पार्टी बन गई है।

विनोद ठाकुर संघ से जुड़े एक कर्मठ भाजपाई रहे हैं । बडसर उपमंडल में संघ के कई बड़े कार्यक्रमों का संचालन वह अपने बलबूते करवाते रहे । भाजपा के कई बड़े कार्यक्रमों में वह बखूबी मंच संचालन करते रहे। विधानसभा चुनाव से पूर्व एक मास्टरस्ट्रोक खेलते हुए वर्तमान विधायक राजेंद्र राणा ने विनोद ठाकुर को वीरभद्र सिंह की मौजूदगी में कांग्रेस में शामिल करवा दिया था । इस बीच विनोद ठाकुर को हमीरपुर सदर से कांग्रेस टिकट देने के भी प्रयास हुए लेकिन बाद में कांग्रेस हाई कमान ने टिकट कुलदीप सिंह पठानिया को दे दिया। इसके बाद विनोद ठाकुर सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र में सक्रीय हो गये जहाँ पूर्व सीएम प्रेम कुमार धूमल व राजेंद्र राणा के बीच काँटे की टक्कर चली हुई थी। धूमल के सुजानपुर सीट 1919 वोटों से हारते ही भाजपा में नया धरुव तैयार हुआ। अब आगामी लोकसभा चुनाव से पहले पूर्व भाजपाइयों की घर वापसी सांसद अनुराग ठाकुर को कितनी मजबूती प्रदान करती है, इस पर सबकी नजर रहेगी।

धूमल पर जिस तरीके के हमले कर विनोद ठाकुर कांग्रेस में शामिल हुए थे, धूमल की हाँ के बिना उनकी घर वापसी मुश्किल लग रही थी। चर्चा है कि भाजपा में शामिल होने के लिए विनोद ठाकुर चार से अधिक बार प्रेम कुमार धूमल से अकेले में मिले और पिछले गिले शिकवे मिटाकर फिर से भाजपा में शामिल होने का रास्ता क्लीयर किया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतपाल सत्ती की मौजूदगी में विनोद ठाकुर आखिर भाजपा में लौट आए ।